देश दर्पण संवाद

— राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक — हम खबर नहीं, आईना दिखाते हैं

अपने लेख या सुझाव भेजने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें

इंदौर, मध्य प्रदेश सोमवार 05 अक्टूबर 2026, कृष्ण पक्ष दशमी - 10, 2083, वर्ष - 1, अंक - 04, पृष्ठ - 8 , मूल्य - रु 2

खराखरा

18 कैरेट : ₹1,15,230
22 कैरेट : ₹1,40,734
24 कैरेट : ₹1,52,872

सकारात्मक सोमवारसर:

सकारात्मक सोमवार
प्रिय पाठकों,
सप्रेमनमस्कार! शुभसोमवार!
आज 'देश दर्पण संवाद' के सफर का यह चौथा सोमवार है, और हमें आपके हाथों में अपना यह चौथा अंक सौंपते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है।
पिछले तीन अंकों के दौरान आप सभी से जो अपार स्नेह, अटूट विश्वास और सकारात्मक मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है, उसने निष्पक्ष और बेबाक पत्रकारिता के प्रति हमारे संकल्प को और भी दृढ़ किया है।
हमारी इस नई शुरुआत को जो मजबूती आपने प्रदान की है, वह आपके समर्थन के बिना संभव नहीं थी। इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं।

मप्र भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में छलका दिग्गजों का दर्द, अफसरों की मनमानी और गुटबाजी पर उठे गंभीर सवाल



भोपाल।

मध्य प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देव और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर तिवारी की मौजूदगी में आयोजित हुई पहली कोर ग्रुप बैठक में सत्ता और संगठन के कामकाज को लेकर नेताओं की तीखी तल्खी सामने आई है।

बैठक के दौरान कई प्रमुख मंत्रियोंने खुले तौर पर अपनी नाराजगी व्यक्त की और नौकरशाही के हावी होने का मुद्दा उठाया।

अधिकारियों के रवैये पर डिप्टी सीएम की शिकायत, सीएम का पलटवार

बैठक में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने अधिकारियों के अड़ियल रवैये पर गंभीर सवाल खड़े किए।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि अफसर हमारी सुन ही नहीं रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं।

एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के घर में घुसने की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे बेहद चिंताजनक करार दिया।

इस शिकायत पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तल्ख लहजे में जवाब देते हुए कहा कि आपके पास महत्वपूर्ण विभाग है, फिर भी 'कफ सिरप' जैसी घटना कैसे हो जाती है?

शिवराज और कैलाश ने भी जताई कड़ी नाराजगी

सत्ता और संगठन के बीच की यह खाई केवल मंत्रियों तक सीमित नहीं रही।

केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि जब वे अपने संसदीय क्षेत्र में आते-जाते हैं, तो वहां के कलेक्टर प्रोटोकॉल तक का पालन नहीं करते हैं।

वहीं,

सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने संवादहीनता का बड़ा मुद्दा उठाया

उन्होंने कहा कि तमाम कोशिशों के बावजूद मुख्यमंत्री से 15-15 दिन तक बात नहीं हो पाती है।

इसके अलावा, मंत्री प्रहलाद पटेल और भाजपा उपाध्यक्ष लाल सिंह ने भी संगठन की मौजूदा स्थिति में सुधार लाने की बात मजबूती से रखी।

प्रदेश प्रभारी की दो टूक: 3 महीने में खत्म करो गुटबाजी, बंद हो जेसीबी से फूल बरसाना

नेताओं की इन शिकायतों और संगठन की हालत को देखते हुए नए प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देव ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने जिला और संभाग प्रभारियों को संगठन के भीतर से गुटबाजी खत्म करने के लिए 3 महीने की 'डेडलाइन' दी है।

उन्होंने निर्देश दिया कि पहले बातचीत और समझाइश से आपसी मतभेद दूर किए जाएं; और यदि फिर भी कोई नेता न माने तो उसका नाम और मोबाइल नंबर सीधे प्रदेश नेतृत्व को भेजा जाए।

साथ ही, प्रदेश पदाधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि दिखावे की राजनीति बंद की जाए। होर्डिंग्स में नेताओं की बड़ी-बड़ी तस्वीरों की जगह सरकारी योजनाओं को प्रमुखता मिलनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, आयोजनों में जेसीबी से फूल बरसाने और महंगे गिफ्ट देने जैसी खर्चीली परंपराओं पर भी तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

पत्रकारिता के उच्च मापदंडों पर खरे उतरने के लिए बप्पा हमें विवेक और शक्ति प्रदान करें, यही हमारी मंगलकामना है। सत्य को सामने लाने की 'देश दर्पण संवाद' की इस नई यात्रा में सुधी पाठकों का स्नेह, समर्थन और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी बनेगा।

देश दर्पण संवाद
हम ख़बर नहीं, आईना दिखाते हैं

34 हजार फीट पर हिम्मत, बचाई 174 जिंदगियां!



नई दिल्ली। 34 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे विमान में जब अचानक खतरा मंडराया, तब 174 यात्रियों की जिंदगी कुछ पलों के फैसले पर टिकी थी। दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार पर उनके को-पायलट ने कथित तौर पर चाकू से हमला किया। विमान नियंत्रण से बाहर होने लगा और करीब दो मिनट में 34 हजार फीट से नीचे 16 हजार फीट तक आ गया।

घायल होने के बावजूद स्मित ने स्थिति संभालने की कोशिश जारी रखी।

घटना का सबसे अहम मोड़ तब आया, जब स्मित ने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही केबिन में मौजूद यात्रियों और क्रू के सदस्य कॉकपिट में पहुंचे और हमलावर को-पायलट को काबू में किया। विमान में मौजूद एक डेंटिस्ट ने घायल कैप्टन का प्राथमिक उपचार किया।

इसके बाद सादे कपड़ों में यात्रा कर रहे दो राहत पायलटों ने विमान की कमान संभाली और उसे सऊदी अरब के ताबुक एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया।

इस घटना के बाद कैप्टन स्मित की बहादुरी की चर्चा भारत से लेकर इजरायल तक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉल के जरिए उनसे करीब 10 मिनट बातचीत की।

बातचीत के दौरान भावुक हुए स्मित ने प्रधानमंत्री से कहा, "आप मेरे हीरो हैं।" उन्होंने बताया कि संकट की उस घड़ी में वह हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। पीएम मोदी ने उनकी सूझबूझ की सराहना करते हुए उनकी मां गीतावेन को अच्छे संस्कार देने के लिए प्रणाम करने की बात कही।

फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने स्मित को राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार देने की मांग की है। वहीं लेखक जावेद अख्तर ने उन्हें महावीर चक्र देने की मांग की है।

अभिनेता आर. माधवन और विजय देवरकोंडा समेत कई हस्तियों ने भी उनकी बहादुरी की सराहना की।

34 हजार फीट पर शुरू हुई यह जद्दोजहद आखिरकार 174 यात्रियों की सुरक्षित जमीन तक पहुंचने के साथ खत्म हुई—और इसके केंद्र में था एक घायल पायलट का वह फैसला, जिसने पूरे घटनाक्रम की दिशा बदल दी।

'आप मेरे हीरो हैं'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाईदुबई के कैप्टन स्मित मच्छार से वीडियो कॉल पर बात कर उनकी बहादुरी की सराहना की। करीब 10 मिनट की बातचीत के दौरान स्मित भावुक हो गए और उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा, **"आपका फोन आना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है... आप मेरे हीरो हैं।"**

स्मित ने उस खौफनाक घटना को याद करते हुए बताया कि जब विमान ने अचानक गोता लगाया, तब उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया।

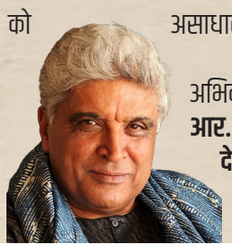
उन्होंने यह भी बताया कि मुश्किल समय में वह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और घटना के दौरान भी यही कर रहे थे।

उनकी बात सुनकर पीएम मोदी ने कहा कि उनके सामने भावुक होने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्मित की सूझबूझ और साहस की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी मां गीतावेन ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्मित के साहस ने कई लोगों की जान बचाई।



बॉलीवुड बोला, असली हीरो स्मित

174 यात्रियों को सुरक्षित बचाने वाले कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी पर फिल्म जगत से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने सरकार से स्मित को **'महावीर चक्र'** देने की मांग की है। उन्होंने विमान में सवार लोगों की जान बचाने के लिए पायलट के साहस को असाधारण बताया।



अभिनेता **सलमान खान, आर. माधवन** और **विजय देवरकोंडा** ने भी सोशल मीडिया पर कैप्टन स्मित की बहादुरी की तारीफ की। फिल्मी पर्दे पर हीरो के किरदार निभाने वाले सितारों ने वास्तविक जिंदगी में यात्रियों की जान बचाने वाले पायलट को असली नायक के तौर पर सराहा।

इधर, सोशल मीडिया पर भी स्मित की बहादुरी को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने भी उन्हें राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की मांग की है।



एक दरवाजा, 174 जिंदगियों का सवाल



फ्लाइट FZ1073 में सबसे निर्णायक क्षण वह था, जब घायल कैप्टन स्मित ने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। **9/11** के बाद विमानन सुरक्षा व्यवस्था में कॉकपिट को यात्रियों और अनधिकृत लोगों से सुरक्षित रखने के लिए दरवाजों की सुरक्षा बेहद कड़ी की गई है। ऐसे में अंदर मौजूद पायलट के नियंत्रण के बिना कॉकपिट तक पहुंचना बेहद मुश्किल होता है।

हमले के बाद विमान तेजी से ऊंचाई खो रहा था। **इसी दौरान स्मित ने दरवाजा अनलॉक किया।** दरवाजा खुलते ही केबिन में मौजूद यात्रियों और क्रू ने कॉकपिट में पहुंचकर हमलावर को-पायलट को काबू किया। विमान में मौजूद एक डेंटिस्ट ने घायल कैप्टन की मदद की।

इसके बाद विमान में मौजूद दो राहत पायलटों ने नियंत्रण संभाला और फ्लाइट को सऊदी अरब के ताबुक एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा। इस तरह एक घायल पायलट का फैसला, यात्रियों की तत्परता और राहत पायलटों की मौजूदगी मिलकर उस संकटपूर्ण उड़ान को सुरक्षित लैंडिंग तक ले गई।

भेल दशहरा मैदान में 35 हजार गोपालकों का सम्मेलन

अमित शाह ने 2029 तक मध्यप्रदेश को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य रखा, गोपालकों की आय बढ़ाने के लिए दूध खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की



भोपाल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आयोजित विशाल सम्मेलन में प्रदेश के किसानों, गोपालकों तथा माताओं-बहनों के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। 11 जिलों के करीब 35 हजार गोपालकों को संबोधित करते हुए उन्होंने लक्ष्य रखा कि 31 दिसंबर 2029 से पहले मध्यप्रदेश को पूरी तरह से नारकोटिक्स (नशा) मुक्त बना दिया जाएगा।

नशामुक्ति के लिए सरकार की बारीक प्लानिंग केंद्रीय मंत्री ने विशेषकर माताओं और अभिभावकों को आश्वस्त करते हुए कहा, "31 दिसंबर 2029 के बाद आपके बेटे-बेटी के लिए मध्यप्रदेश में नशे की जगह ही नहीं होगी, उनका उज्ज्वल भविष्य होने वाला है"।

उन्होंने बताया कि इसके लिए मुख्यमंत्री और गृह विभाग के साथ मिलकर बारीक प्लानिंग की जा रही है। प्रदेश में ड्रग्स के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं; हाल ही में भोपाल में 1,814 करोड़ रुपये की 90 किलो एमडी ड्रग्स (सिंथेटिक ड्रग्स) पकड़ी गई थी। वहीं, 2015 से 2024 के बीच प्रदेश में 28,178 एनडीपीएस (NDPS) केस दर्ज किए जा चुके हैं।

सहकारिता मंत्रालय से गोपालकों की आय में सीधा इजाफा

कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए शाह ने कहा कि देश आजाद होने के बाद से ही स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की मांग थी, लेकिन कांग्रेसियों ने 75 साल तक इसे बनने नहीं दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की, जिसका सबसे बड़ा फायदा गोपालकों को मिलने वाला है। उन्होंने घोषणा की कि को-ऑपरेटिव व्यवस्था में दूध भरने पर पहले ही दिन से 35 रुपये की जगह 55 रुपये मिलने की शुरुआत हो जाएगी।

44 साल का वनवास खत्म: भारत की बेटियों ने रचा स्वर्णिम इतिहास, चीन का गुरूर तोड़ा



दिल्ली। एशियन गेम्स के खिताबी मुकाबले में भारतीय महिला हॉकी टीम ने वो कर दिखाया है, जिसका पूरे देश को 44 वर्षों से इंतजार था। जापान में खेले गए बेहद दबाव वाले फाइनल मुकाबले में भारत की बेटियों ने अपने अदम्य साहस, अभेद्य डिफेंस और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए डिफेंडिंग चैंपियन चीन को 1-0 से हराकर स्वर्ण पदक पर ऐतिहासिक क जा जमा लिया है। इस स्वर्णिम जीत के साथ ही भारतीय टीम ने लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 के लिए भी सीधे क्वालीफाई कर लिया है।

शुरुआत में ही प्रहार, लालरेम्सियामी का अचूक निशाना

खिताबी मुकाबले में भारत ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। मैच के पहले क्वार्टर के 10वें मिनट में ही स्टार फॉरवर्ड लालरेम्सियामी ने चीनी डिफेंस को चकमा दिया और एक शानदार रिवर्स-हिट के जरिए गेंद को नेट में उलझा दिया। यह इकलौता गोल ही अंततः निर्णायक साबित हुआ और भारत को जीत की राह पर ले गया।

जब चीन के सामने 'दीवार' बन गईं सविता पूनिया

मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट और सांसें रोक देने वाला पल दूसरे क्वार्टर के 23वें मिनट में आया, जब चीन को बराबरी करने का एक सुनहरा मौका पेनल्टी स्ट्रोक के रूप में मिला। उस वक्त पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था, लेकिन भारतीय गोलपोस्ट के सामने अडिग खड़ीं दिग्गज गोलकीपर सविता पूनिया ने इस जोरदार प्रहार को अविश्वसनीय फुर्ती से रोककर चीन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अंतिम मिनटों का महा-रोमांच और अभेद्य डिफेंस

मैच के अंतिम क्षणों में हताश चीन ने अपने गोलकीपर को मैदान से बाहर बुलाकर 11 आउटफील्ड खिलाड़ियों के साथ भारत पर चौतरफा हमले किए। यह रणनीति किसी भी टीम पर भारी पड़ सकती थी, लेकिन कप्तान सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय डिफेंस ने एक किले की तरह चीन के हर वार को नाकाम कर दिया।

फाइनल हूटर बजते ही मैदान पर तिरंगा लहरा उठा और

चार दशक बाद एशियाई खेलों में भारत के राष्ट्रगान की गूंज सुनाई दी। एशियन गेम्स के 13वें दिन इस ऐतिहासिक जीत के साथ भारत के खाते में 6 गोल्ड मेडल आ चुके हैं।

एक नज़र में फाइनल का रोमांच

गोल चेंजर
10वें मिनट में लालरेम्सियामी का रिवर्स-हिट से किया गया विजयी गोल।

गोल चेंजर
23वें मिनट में गोलकीपर सविता पूनिया द्वारा पेनल्टी स्ट्रोक का अचूक बचाव।

गोल चेंजर
इस गोल्ड मेडल के साथ भारतीय टीम को लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 का डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिला।

छोटे तालाब में रोज पहुंच रहा 8 एमएलडी सीवेज, नगर निगम पर 2.10 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आकलन



● अभिषेक राणा

भोपाल, राजधानी भोपाल के छोटे तालाब में अब भी बिना उपचारित सीवेज पहुंचने का मामला सामने आया है। नगर निगम द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार बाणगंगा नाले और एक अन्य नाले से करीब 8 एमएलडी सीवेज सीधे छोटे तालाब में मिल रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार बाणगंगा नाले से करीब 6 एमएलडी और पुराने मछलीघर के पास से लगभग 2 एमएलडी सीवेज तालाब में जा रहा है। पहले चिन्हित 37 नालों को इंटरसेप्ट करके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की ओर डायवर्ट किए जाने की जानकारी भी दी गई है। इसके बावजूद इन दो स्रोतों से सीवेज का प्रवाह जारी है।

इस मामले में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 31 मार्च से 31 दिसंबर 2027 तक की 21 महीने की अवधि के लिए 2.10 करोड़ रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आकलन किया है। हालांकि यह राशि अभी NGT द्वारा अंतिम रूप से तय किया गया जुर्माना नहीं है। नगर निगम ने NGT को बताया कि सीवेज के उपचार के लिए 10 एमएलडी क्षमता वाले नए STP का निर्माण शुरू हो चुका है। इसका काम 11 सितंबर 2026 को शुरू हुआ और इसे 31 दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

NGT ने नगर निगम से जलस्रोत और वेटलैंड की सुरक्षा तथा अनुपचारित पानी की निकासी रोकने को लेकर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होनी है।

राजधानी में खास

मिंटो हॉल से निकली 'ट्रेजर हंट कार रैली', सुराग तलाशते हुए पर्यटन स्थलों तक पहुंचे शहरवासी

पर्यटन, पहेलियां और रफ्तार का अनोखा संगम



● प्रकाश त्रिपाठी

भोपाल। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर राजधानी भोपाल के पर्यटन स्थलों को एक्सप्लोर करने का एक बिल्कुल नया और रोमांचक अंदाज देखने को मिला।

'भोपाल सिटी लाइव' और **'मध्य प्रदेश टूरिज्म'** के साझा प्रयासों से ऐतिहासिक मिंटो हॉल से 'ट्रेजर हंट कार रैली- सीजन 2' का भव्य आयोजन हुआ।

इस रैली ने न केवल शहरवासियों में रोमांच भरा, बल्कि पहेलियों के दिलचस्प ताने-बाने के जरिए उन्हें अपने ही शहर की पर्यटन विरासतों से एक मनोरंजक तरीके से जोड़ दिया।

जुम्बा की ऊर्जा और पहेलियों का रोमांच कार्यक्रम की शुरुआत एक ऊर्जा से भरे जुम्बा सेशन के साथ हुई। इसके बाद प्रतिभागियों को नियम समझाकर मिंटो हॉल से कार रैली को हरी झंडी दिखाई गई। इस रैली का सबसे मजेदार पहलू यह था कि प्रतिभागियों को किसी भी गंतव्य का सीधा रास्ता नहीं बताया गया।

उन्हें पर्यटन स्थलों तक पहुंचने के लिए दिलचस्प सुराग (क्लू) और पहेलियां दी गईं थीं। अपनी टीम के साथ मिलकर दिमाग दौड़ाते और पहेलियां सुलझाते हुए जब प्रतिभागी सही ठिकानों पर पहुंचे, तो उनका उत्साह देखते ही बनता था।

इस पूरी तकनीकी भूलभुलैया और रैली संचालन का जिम्मा 'जीनियस ग्रुप' के नीरज गुलाटी ने बेहद सधे हुए अंदाज में संभाला, वहीं 'इवेंट ट्री' की कल्पना दिलोरी के शानदार इवेंट मैनेजमेंट ने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद रखा।

दिग्गजों ने दिखाई हरी झंडी

रैली के शुभारंभ अवसर पर सीआई हुंडई के संचालक राकेश मलिक, आकाश मलिक और एमपी टूरिज्म की नीलम रावत ने झंडी दिखाकर प्रतिभागियों को रवाना किया।

इस खास मौके पर एसपी रेडियो के शशांक गर्ग, आईडीबीआई बैंक के सुरेश राठौड़, लक्ष्मीपति ग्रुप के संजय बंसल, लिबर्टी इंश्योरेंस के हेड रितेश सिंह, तिरुपति बालाजी वेयरहाउसेस के जितेंद्र मीना व विशाल वर्मा और 'भोपाल सिटी लाइव' के संस्थापक एडवोकेट आनंद शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे।

गरिमा-अमित बने सिकंदर, डॉ. श्रद्धा का स्लोगन रहा बेस्ट

सुरागों की खोजबीन का यह रोमांचक सफर वापस मिंटो हॉल में संपन्न हुआ, जहां स्वादिष्ट नाश्ते के साथ प्रतिभागियों की थकान मिटाई गई।

रचनात्मकता को परखने के लिए यहां 'एमपी टूरिज्म थीम स्लोगन प्रतियोगिता' भी रखी गई।

पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी और विशेष अतिथि हरिओम जटिया ने विजेताओं को सम्मानित किया।

कड़ी टक्कर के बीच ट्रेजर हंट कार रैली में गरिमा निचलानी और अमित अग्रवाल संयुक्त विजेता (Joint Winners) बनकर उभरे, जिन्हें 21,000 रुपये की नकद इनामी राशि और चमचमाती ट्रॉफी सौंपी गई। वहीं, सागर मेंघानी ने तीसरा स्थान पक्का कर ट्रॉफी अपने नाम की।

दूसरी ओर, स्लोगन प्रतियोगिता में डॉ. श्रद्धा झुनझुनवाला ने बाजी मारते हुए पहला स्थान पाया, जबकि ज्योति परिहार फर्स्ट रनर-अप और डॉ. वैशाली थारानी सेकंड रनर-अप रहीं।

आयोजन के अंत में एडवोकेट आनंद शर्मा ने इस सफल आयोजन के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म सहित सभी सहयोगियों, प्रायोजकों और आयोजन टीम का हृदय से आभार जताया। कार ड्राइव, टीमवर्क और शहर की खोज का यह कॉकटेल भोपालवासियों के लिए एक बेहद यादगार अनुभव बन गया।



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेशभर में हो रहे विविध आयोजन; स्वच्छता कर्मियों का हुआ सम्मान, लिया गया 'प्लास्टिक मुक्त परिसर' का संकल्प

मध्य प्रदेश में 'सेवा संकल्प अभियान 2026' का शंखनाद : 2 से 10 अक्टूबर तक चलेगा जन-सेवा का महाभियान



भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने आम जनमानस को स्वच्छता और समाज सेवा से गहराई से जोड़ने के लिए 'सेवा संकल्प अभियान-2026' का व्यापक स्तर पर शुभारंभ किया है।

"सेवा का संकल्प, जन-जन का योगदान" के मूल मंत्र पर आधारित यह विशेष अभियान 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2026 तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। जनसंपर्क मध्य प्रदेश की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इस 9 दिवसीय 'सेवा मेरा योगदान' अभियान के तहत राज्य के सभी हिस्सों में विविध जन-सेवा गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

स्वच्छता वीरों का सम्मान और प्लास्टिक मुक्त परिसर का संकल्प अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर के अवसर पर की गई, जिसमें पूरे प्रदेश में दो प्रमुख विषयों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।

पहला, समाज को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने में दिन-रात एक करने वाले स्वच्छता कर्मियों के अमूल्य योगदान को सराहते हुए, प्रदेशभर में उनका विशेष सम्मान किया गया। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास की दिशा में कदम बढ़ाते हुए परिसरों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए सामूहिक संकल्प लिया गया।

'जन सेवा से देश सेवा' की प्रेरणा

यह वृहद अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सुशासन और सेवा कार्यों (जन सेवा से देश सेवा) से सीधे तौर पर प्रेरित है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार इस अभियान के जरिए यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश का हर एक नागरिक सेवा कार्यों में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाए।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी प्रयासों को एक बड़े जन-आंदोलन में बदलना है, ताकि स्वच्छता और सेवा समाज के स्वभाव का स्थायी हिस्सा बन सकें।

मध्य प्रदेश में संगठित सार्वजनिक बस परिवहन व्यवस्था को दो दशक से अधिक समय बाद फिर शुरू किया गया

21 साल बाद मध्य प्रदेश में लौटी सरकारी बस सेवा, पहले चरण में 351 बसें सड़कों पर



● हिमांशु मिश्रा

भोपाल : मध्य प्रदेश में संगठित सार्वजनिक बसपरिवहन व्यवस्था को दो दशक से अधिक समय बाद फिर शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भोपाल के भेल दशहरा मैदान से नई बस सेवा की शुरुआत की।

हालांकि इसका उद्घाटन 26 सितंबर को हुआ था, 28 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच यह नई परिवहन व्यवस्था प्रदेश में चर्चा का प्रमुख विषय बनी रही, इसलिए इसे आपकी समाचार सूची में शामिल किया जा सकता है।

नई व्यवस्था के पहले चरण में कुल 351 बसें शामिल की गई हैं। इनमें 120 इंटरसिटी और 231 इंट्रासिटी बसें हैं। बसों का संचालन सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल के माध्यम से किया जाएगा।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार इंदौर को सबसे अधिक 145 बसें, भोपाल को 106 और जबलपुर को 67 बसें मिली हैं। इसके अलावा रीवा को 18, देवास को 10, कटनी को 3 और भिंड को 2 बसें आवंटित की गई हैं।

यह व्यवस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी MPSRTC को वर्ष 2005 में बंद कर दिया गया था। उस समय निगम पर लगभग 756 करोड़ रुपये की देनदारियां थीं और उसे हर महीने करीब 5 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा था। नई व्यवस्था पुराने निगम के मॉडल से अलग होगी।

इसमें निजी ऑपरेटर सरकारी नियमन के तहत बसों का संचालन करेंगे।

राज्य सरकार ने पहले वर्ष में बस नेटवर्क को लगभग 1,500 बसों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद हर साल 2,500 से 3,000 बसें जोड़ने की योजना बताई गई है। दीर्घकालिक लक्ष्य वर्ष 2031 तक लगभग 15,000 बसों का नेटवर्क तैयार करना है।

नई बस व्यवस्था में यात्रियों की सुरक्षा और निगरानी पर भी जोर दिया गया है। बसों में CCTV कैमरे, पैनिक बटन और वाहन लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। बसों की निगरानी के लिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बसों की सुरक्षा और फिटनेस को लेकर अधिकारियों तथा निर्माताओं को निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में देशभर में बस दुर्घटनाओं में करीब 3,800 लोगों की मौत हुई थी।

मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन पर भी जोर दिया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य के लिए 972 इलेक्ट्रिक बसें मंजूर की गई हैं, जबकि राज्य की संभावित जरूरत लगभग 25 हजार इलेक्ट्रिक बसों की बताई गई है।

नई व्यवस्था के तहत बसों के संचालन, रूट और किराये को लेकर भी एक केंद्रीकृत निगरानी व्यवस्था विकसित की जा रही है। सरकार का उद्देश्य केवल शहरों के भीतर परिवहन सुविधा बढ़ाना नहीं, बल्कि छोटे शहरों और जिला मुख्यालयों को भी बेहतर बस नेटवर्क से जोड़ना है।

इससे उन यात्रियों को फायदा मिलने की उम्मीद है जो निजी वाहनों या अनियमित निजी बस सेवाओं पर निर्भर रहते हैं।

सरकार की योजना के अनुसार आने वाले चरणों में बस सेवा का विस्तार प्रदेश के अन्य शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों तक किया जाएगा। इंटरसिटी बसों के जरिए अलग-अलग जिलों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर रहेगा, जबकि इंट्रासिटी बसें शहरों के भीतर यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराएंगी।

अधिकारियों के मुताबिक नए रूट तय करते समय यात्रियों की संख्या, प्रमुख बाजारों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक क्षेत्रों को ध्यान में रखा जाएगा।

नई बस सेवा में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

यात्रियों को बसों की लोकेशन, संभावित आगमन समय और रूट की जानकारी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की जा रही है। इससे यात्रियों को बस के इंतजार में लंबे समय तक खड़े रहने की समस्या कम करने में मदद मिल सकती है।

राज्य में सार्वजनिक परिवहन के विस्तार का एक महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं, विद्यार्थियों और रोजाना काम के लिए यात्रा करने वाले लोगों की आवाजाही भी है। बड़े शहरों में निजी वाहनों की बढ़ती संख्या के बीच सार्वजनिक बसों का नेटवर्क मजबूत होने से सड़क पर वाहनों का दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।

हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव बसों की नियमितता, रूट कवरेज, किराये और संचालन की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा। इलेक्ट्रिक बसों को लेकर भी राज्य सरकार की योजना महत्वपूर्ण है।

972 स्वीकृत इलेक्ट्रिक बसें आने वाले समय में सार्वजनिक परिवहन को अपेक्षाकृत कम-उत्सर्जन वाले विकल्प की ओर ले जाने में मदद कर सकती हैं। इसके लिए चार्जिंग स्टेशन, डिपो और रखरखाव की पर्याप्त व्यवस्था भी जरूरी होगी।

सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य 2031 तक लगभग 15 हजार बसों का नेटवर्क तैयार करना है। यदि यह लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से लागू होता है, तो प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन का दायरा वर्तमान शुरुआती नेटवर्क की तुलना में काफी बढ़ जाएगा।

हालांकि इस विस्तार की सफलता बसों की उपलब्धता के साथ-साथ उनके नियमित संचालन, सुरक्षित यात्रा, समयपालन और यात्रियों के लिए सुलभ किराये पर निर्भर करेगी।

शहर	आवंटित बसें
इंदौर	145
भोपाल	106
जबलपुर	67
रीवा	18
देवास	10
कटनी	03
भिंड	02
कुल	351

पुतिन बोले- यूक्रेन विवाद सुलझाने के लिए पीएम मोदी के पास बेहतरीन विचार

अंतरराष्ट्रीय मंच पर गूंजी भारत की शांति नीति



मास्को/नई दिल्ली।
रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच शांति बहाली की कोशिशों में भारत की कूटनीति को बड़ा समर्थन मिला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अंतरराष्ट्रीय मंच 'वाल्दाई डिस्कशन क्लब' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शांति प्रयासों की खुलकर सराहना की है। पुतिन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब रूस-यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं।
राष्ट्रपति पुतिन ने वैश्विक मंच से कहा कि यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास व्यावहारिक और सकारात्मक विचार हैं। रूसी राष्ट्रपति ने यह भी रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मुलाकातों और बातचीत के दौरान रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने तथा शांति बहाल करने के मुद्दे को गंभीरता से उठाते रहे हैं।
पुतिन की टिप्पणी भारत और रूस के बीच जारी उच्चस्तरीय संपर्क के बीच आई है। भारत ने युद्ध की शुरुआत के बाद से लगातार बातचीत और कूटनीति के जरिए विवाद के समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया है। नई दिल्ली ने कई मौकों पर यह स्पष्ट किया है कि किसी भी संघर्ष का स्थायी समाधान बातचीत और कूटनीतिक माध्यमों से ही संभव है।
भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अपने राजनयिक संबंध बनाए रखे हैं। युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की रूसी और यूक्रेनी नेतृत्व के साथ हुई मुलाकातों और बातचीत को इसी संदर्भ में देखा गया है। भारत ने सार्वजनिक रूप से दोनों पक्षों के बीच संवाद और कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है।
पुतिन ने अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री जब भी अंतरराष्ट्रीय नेताओं के साथ बातचीत करते हैं, तो यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का मुद्दा उठाते हैं। रूस की ओर से मोदी के प्रयासों की यह सार्वजनिक प्रशंसा भारत की कूटनीतिक भूमिका के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
रूस-यूक्रेन युद्ध केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं रहा है। इसके प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़े हैं। ऐसे में युद्ध को समाप्त करने के लिए होने वाले किसी भी कूटनीतिक प्रयास का असर व्यापक स्तर पर पड़ सकता है।
भारत ने इस पूरे संकट के दौरान अपने रणनीतिक हितों और स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखने की कोशिश की है। एक तरफ भारत के रूस के साथ लंबे समय से रक्षा, ऊर्जा और रणनीतिक संबंध हैं, वहीं दूसरी ओर यूरोप और पश्चिमी देशों के साथ भी भारत के आर्थिक और कूटनीतिक संबंध लगातार महत्वपूर्ण बने हुए हैं। इस संतुलन ने भारत की विदेश नीति को अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बनाया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन दोनों की अपनी यात्राओं के दौरान शांति और संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया था। भारत की ओर से यह संदेश दिया जाता रहा है कि युद्ध के मैदान में किसी भी संघर्ष का स्थायी समाधान हासिल करना कठिन है और बातचीत के जरिए ही आगे बढ़ने का रास्ता निकाला जा सकता है।
पुतिन का ताजा बयान इसी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के बीच आया है। रूसी राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के विचारों को व्यावहारिक और सकारात्मक बताना भारत की शांति संबंधी पहलों को लेकर रूस की सार्वजनिक स्थिति को दर्शाता है। हालांकि, रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों की सहमति और ठोस वार्ता अभी भी महत्वपूर्ण बनी हुई है।
भारत की भूमिका को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार चर्चा होती रही है। भारत ने युद्ध के समाधान के लिए किसी एक पक्ष का सैन्य समर्थन करने के बजाय संवाद, कूटनीति और शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया है। इसी वजह से रूस-यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में नई दिल्ली के संदेशों को वैश्विक कूटनीति में विशेष महत्व दिया जाता है।
पुतिन की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है और युद्ध को समाप्त करने के लिए विभिन्न स्तरों पर बातचीत तथा कूटनीतिक विकल्पों पर चर्चा होती रही है। ऐसे में भारत की ओर से संवाद और शांति पर जोर देना उसकी विदेश नीति के प्रमुख संदेशों में बना हुआ है।

रूसी राष्ट्रपति की टिप्पणी को भारत-रूस संबंधों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में लंबे समय से सहयोग रहा है। वहीं भारत पश्चिमी देशों के साथ भी अपने संबंधों को लगातार मजबूत कर रहा है। ऐसे वैश्विक माहौल में रूस और पश्चिम के बीच संतुलन बनाए रखना भारत की विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण चुनौती भी है।
फिलहाल पुतिन का बयान इस बात को रेखांकित करता है कि रूस भारत के शीर्ष नेतृत्व की शांति संबंधी पहलों को सार्वजनिक रूप से सकारात्मक नजरिए से देखता है। हालांकि युद्ध का अंतिम समाधान रूस और यूक्रेन के बीच प्रत्यक्ष राजनीतिक बातचीत, सुरक्षा संबंधी चिंताओं और दोनों पक्षों की सहमति पर निर्भर करेगा। ऐसे में भारत की कूटनीतिक सक्रियता आने वाले समय में भी अंतरराष्ट्रीय निगाहों में बनी रहने की संभावना है।

अंतरिक्ष में गूंजेगा भारत का डंका

देश का पहला कंप्यूटिंग सैटेलाइट 'MOI-1A' लॉन्च के लिए तैयार
स्पेसएक्स के मिशन के साथ उड़ान भरेगा भारतीय स्टार्टअप 'TakeMe2Space' का उपग्रह

नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान और निजी स्पेस इकोसिस्टम के लिए एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। देश के अग्रणी निजी स्पेस स्टार्टअप 'TakeMe2Space' ने भारत का पहला कंप्यूटिंग सैटेलाइट 'MOI-1A' तैयार किया है। इसे स्पेसएक्स के Transporter-18 राइडशेयर मिशन के जरिए पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया। यह मिशन भारत के तेजी से विकसित हो रहे निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण तकनीकी कदम माना जा रहा है।
इस महत्वाकांक्षी उपग्रह की सबसे खास विशेषता इसकी अंतरिक्ष में ही डेटा प्रोसेस करने की क्षमता है। पारंपरिक उपग्रहों में बड़ी मात्रा में कच्चा डेटा पृथ्वी पर स्थित ग्राउंड स्टेशनों तक भेजा जाता है, जिसके बाद कंप्यूटर और एआई सिस्टम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। MOI-1A इस प्रक्रिया को बदलने की कोशिश करता है। उपग्रह में मौजूद एज-कंप्यूटिंग प्रोसेसर डेटा का विश्लेषण अंतरिक्ष में ही कर सकते हैं और जरूरत के मुताबिक केवल उपयोगी परिणाम पृथ्वी पर भेजे जा सकते हैं। इससे बड़े पैमाने पर कच्चा डेटा ट्रांसफर करने की जरूरत कम हो सकती है।
MOI-1A का वजन 50 किलोग्राम से कम बताया गया है और इसमें Nvidia Orin NX एज-कंप्यूटिंग प्रोसेसर लगाए गए हैं। कंपनी के अनुसार इस मिशन के लिए उसके साथ 23 ग्राहक जुड़े हैं।
इनमें भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS), कृषि, खनन, सप्लाई चेन और बीमा जैसे क्षेत्रों से जुड़े संगठन शामिल हैं। इसका मतलब है कि इस तकनीक का इस्तेमाल केवल अंतरिक्ष अनुसंधान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यावसायिक और औद्योगिक जरूरतों के लिए भी किया जा सकता है।
उदाहरण के तौर पर कृषि क्षेत्र में उपग्रह किसी इलाके की तस्वीरों का विश्लेषण कर फसल की स्थिति से संबंधित जानकारी तैयार कर सकता है। इसी तरह खनन कंपनियों के लिए किसी क्षेत्र में बदलाव की पहचान, बीमा कंपनियों के लिए फसल या संपत्ति से संबंधित नुकसान का आकलन और सप्लाई चेन कंपनियों के लिए दूरदराज के क्षेत्रों की निगरानी जैसे कार्यों में ऑर्बिटल कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसका उद्देश्य हर तस्वीर और हर डेटा को पृथ्वी पर भेजने के बजाय वहीं आवश्यक जानकारी निकालना है। TakeMe2Space की यह परियोजना पूरी तरह से अचानक सामने नहीं आई है। कंपनी ने इससे पहले MOI-TD नामक तकनीकी प्रदर्शन मिशन के जरिए अंतरिक्ष में एआई आधारित डेटा प्रोसेसिंग की क्षमता का परीक्षण किया था।
उस मिशन में पृथ्वी से एप्लिकेशन अपलोड करने, उन्हें कक्षा में चलाने और परिणाम वापस पृथ्वी पर भेजने की क्षमता का परीक्षण किया गया था। कंपनी के अनुसार इस परीक्षण ने आगे के ऑर्बिटल कंप्यूटिंग मिशनों के लिए तकनीकी आधार तैयार किया।
MOI-1A को कंपनी की इसी तकनीक को व्यावसायिक स्तर पर आगे बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। कंपनी के संस्थापक और CEO Ronak Samantray के अनुसार, अंतरिक्ष में ही डेटा को प्रोसेस करने से उन ग्राहकों के लिए लागत और समय दोनों कम किए जा सकते हैं जिन्हें बड़ी मात्रा में सैटेलाइट डेटा डाउनलोड करना पड़ता है।
इस मॉडल में ग्राहक अपने एआई मॉडल उपग्रह पर चला सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार विश्लेषित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।
इस मिशन का महत्व भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के विस्तार से भी जुड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स ने सैटेलाइट निर्माण, लॉन्च सेवाओं, पृथ्वी अवलोकन और अंतरिक्ष आधारित डेटा सेवाओं जैसे क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं।



आरएसएस ने देशभर में एनआरसी लागू करने की मांग की



नई दिल्ली:
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू करने की मांग की है। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा है कि देश में यह पहचान होना आवश्यक है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं।
आंबेकर का यह बयान आगामी जनगणना और 'स्मार्ट आइडेंटिटी रजिस्टर' (SIR) को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच आया है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से देश के मूल नागरिकों और अवैध प्रवासियों के बीच अंतर स्पष्ट होना चाहिए। संघ का मत है कि बिना आधिकारिक पहचान के किसी को भी देश में बसने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।
वर्तमान में केंद्र सरकार नई जनगणना प्रक्रिया और नागरिकों का डेटाबेस (जैसे SIR) तैयार करने की रूपरेखा पर काम कर रही है, जिस पर विभिन्न राजनीतिक दलों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
इसी संदर्भ में आरएसएस ने स्पष्ट किया है कि वह पूरे देश में एनआरसी लागू करने के पक्ष में है।

सरसंघचालक ने स्पष्ट किया- धर्म और राष्ट्र अलग-अलग ईकाइयां नहीं; राष्ट्र की अखंडता और परम वैभव के लिए सनातन मूल्यों का संरक्षण अनिवार्य

धर्म और राष्ट्र एक-दूसरे के पूरक, धर्म पर संकट आया तो देश को भुगतना होगा खामियाजा: डॉ. मोहन भागवत

नागपुर।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने राष्ट्र और धर्म के अंतर्संबंधों पर गहरा विमर्श प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया है कि भारत के संदर्भ में धर्म और राष्ट्र कोई दो पृथक इकाइयां नहीं हैं।
उन्होंने देशवासियों को आगाह करते हुए कहा है कि यदि कभी धर्म पर कोई संकट आता है, तो उसका सीधा और गंभीर परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। यह वक्तव्य केवल एक बयान नहीं, बल्कि राष्ट्र की वर्तमान दशा और दिशा को लेकर एक गंभीर चिंतन है।

धर्म ही है राष्ट्र की मूल चेतना
सरसंघचालक के अनुसार, राष्ट्र का समग्र अस्तित्व केवल उसकी भौगोलिक सीमाओं से नहीं, बल्कि उसके 'धर्म' अर्थात शाश्वत कर्तव्यों, नैतिकता और सांस्कृतिक जीवन मूल्यों से तय होता है। भारत की मूल पहचान ही उसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना में रची-बसी है।
यदि समाज में धर्म का ह्रास होता है, तो राष्ट्र का बुनियादी ढांचा स्वत: ही कमजोर पड़ने लगता है। धर्म के बिना एक सशक्त राष्ट्र की कल्पना उसी प्रकार अधूरी है, जैसे प्राण के बिना शरीर। दोनों एक-दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हैं।

अलगाव की दृष्टि अव्यावहारिक और घातक
संघ प्रमुख का यह वक्तव्य उन तमाम वैचारिक विमर्शों का मुखर उत्तर है, जो धर्म और राष्ट्र को अलग-अलग खांचे में रखकर देखने की वकालत करते हैं। संघ की यह स्पष्ट मान्यता रही है कि भारत का 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' ही उसे दुनिया के अन्य देशों से विशिष्ट बनाता है।
डॉ. भागवत ने इसी वैचारिक धरातल को पुष्ट करते हुए कहा कि जब तक समाज में धर्म जीवित, जागृत और सुरक्षित है, तब तक राष्ट्र की प्रगति और अखंडता को कोई बाह्य या आंतरिक शक्ति बाधित नहीं कर सकती। राष्ट्र के बिना धर्म का संरक्षण कठिन है और धर्म के बिना राष्ट्र का उत्थान असंभव है।

वर्तमान चुनौतियों के बीच समाज को संदेश
आज जब देश के भीतर और बाहर कई प्रकार की वैचारिक, जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक चुनौतियां आकार ले रही हैं, ऐसे में आरएसएस प्रमुख का यह बयान एक दिशा-निर्देशक की भूमिका निभाता है।
यह समाज से अपनी जड़ों की ओर लौटने, एकजुट रहने और अपने राष्ट्रीय व धार्मिक कर्तव्यों के प्रति सचेत रहने का आह्वान है। यह स्पष्ट करता है कि भारत की राष्ट्रीयता और उसके उज्ज्वल भविष्य का मार्ग, उसके सनातन मूल्यों और धर्म के संरक्षण से होकर ही गुजरता है।
एक सशक्त, सुरक्षित और परम वैभव संपन्न राष्ट्र के निर्माण के लिए समाज को धर्म-रक्षा के प्रति अपनी जवाबदेही समझनी होगी। राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में धर्म को हाशिए पर नहीं रखा जा सकता; धर्म सुरक्षित रहेगा, तभी यह देश विश्व पटल पर अपना सही स्थान ग्रहण कर सकेगा।



रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता भारत, स्वदेशी उत्पादन ने बनाया नया रिकॉर्ड

नई दिल्ली। भारत का रक्षा क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में आयात पर निर्भर देश से स्वदेशी उत्पादन और निर्यात की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' नीति के तहत घरेलू कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों को बढ़ावा मिलने से देश में तैयार होने वाले सैन्य उपकरणों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है।
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा उत्पादन करीब 1.50 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। इसी अवधि में रक्षा निर्यात भी बढ़कर लगभग 23,622 करोड़ रुपये हो गया। भारत अब 100 से ज्यादा देशों को रक्षा उत्पाद और उपकरण निर्यात कर रहा है।
इस बदलाव का महत्व केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन का सीधा संबंध देश की रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा से है। लंबे समय तक भारत अपनी सैन्य जरूरतों के लिए विदेशी देशों पर काफी निर्भर रहा।
ऐसे में घरेलू स्तर पर मिसाइल, तोप, हेलिकॉप्टर, रडार, युद्धपोत और दूसरे आधुनिक सैन्य उपकरण तैयार होना सुरक्षा के लिहाज से बड़ा बदलाव है।
सरकार ने रक्षा खरीद में घरेलू कंपनियों को प्राथमिकता देने, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और रक्षा अनुसंधान में निवेश को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है। इससे देश में नई तकनीक और रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं।
भारत के लिए अगली चुनौती इस रफ्तार को बनाए रखना है। अगर स्वदेशी तकनीक और उत्पादन क्षमता लगातार बढ़ती रही, तो भारत न केवल अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए अधिक आत्मनिर्भर होगा, बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार में एक महत्वपूर्ण निर्यातक देश के रूप में भी अपनी जगह मजबूत कर सकता है





रवि शुक्ला, (सीधी जिला, पत्रकार)

“यूपी की करवट में छिपी है राष्ट्रीय राजनीति की आहट”

उत्तर प्रदेश की राजनीति केवल 403 विधानसभा सीटों का गणित नहीं है। यह देश की सत्ता के मानस को प्रभावित करने वाली वह राजनीतिक धुरी है, जिसके इर्द-गिर्द राष्ट्रीय राजनीति की अनेक दिशाएं तय होती रही हैं। वर्ष 2027 में होने वाला उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव इसलिए महज सत्ता परिवर्तन या सत्ता की निरंतरता का चुनाव नहीं होगा, बल्कि यह सामाजिक समीकरणों, विकास की राजनीति, आरक्षण, रोजगार, कानून-व्यवस्था और राजनीतिक नैरेटिव की भी परीक्षा होगा।

उत्तर प्रदेश विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल मई 2027 में समाप्त होना है। इसके साथ ही राज्य की राजनीतिक जमीन पर अभी से गतिविधियां तेज होना स्वाभाविक है। राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती केवल मतों को अपने पक्ष में करना नहीं, बल्कि अलग-अलग सामाजिक समूहों के बीच अपनी स्वीकार्यता का विस्तार करना होगी।

2024 के लोकसभा चुनाव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 33 सीटें मिलीं, जबकि समाजवादी पार्टी ने 37 और कांग्रेस ने छह सीटें जीतीं। परिणाम ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश का मतदाता किसी एक राजनीतिक ध्रुव में पूरी तरह बंधा हुआ नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा 255 सीटों और लगभग 41.29 प्रतिशत मत के साथ सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई थी, जबकि सपा को 111 सीटें और लगभग 32.06 प्रतिशत मत मिले थे। यही कारण है कि 2027 का चुनाव सरल समीकरणों से समझना कठिन होगा।

आरक्षण और यूजीसी की बहस बनेगी महत्वपूर्ण मुद्दा

इन दिनों उच्च शिक्षा, आरक्षण और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दे राजनीतिक विमर्श में प्रमुखता पा रहे हैं। यूजीसी ने जनवरी 2026 में उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने से संबंधित नए नियम जारी किए हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने और समान अवसर सुनिश्चित करने की व्यवस्था पहले से ही नियामकीय ढांचे का हिस्सा रही है।

लेकिन राजनीतिक प्रश्न यह है कि इन नीतियों को समाज के विभिन्न वर्ग किस रूप में देखते हैं। सामान्य वर्ग के एक हिस्से में आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की मांग लंबे समय से उठती रही है, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को सामाजिक प्रतिनिधित्व और ऐतिहासिक असमानता दूर करने का संवैधानिक माध्यम माना जाता है।

यहीं से राजनीति का सबसे संवेदनशील प्रश्न सामने आता है—समान अवसर और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन कैसे स्थापित हो?

यदि राजनीतिक दल इस प्रश्न का उत्तर केवल नारों से देंगे तो सामाजिक विभाजन बढ़ सकता है। लेकिन यदि वे शिक्षा, रोजगार, आर्थिक अवसर और संवैधानिक अधिकारों के संदर्भ में ठोस नीतिगत प्रस्ताव रखते हैं तो चुनावी बहस अधिक सार्थक हो सकती है।

सवर्ण असंतोष बनाम सामाजिक न्याय

उत्तर प्रदेश में लंबे समय से भाजपा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक आधार सामान्य वर्ग के मतदाताओं में रहा है।

ऐसे में यूजीसी, आरक्षण और एससी-एसटी कानून से जुड़े विवादों पर उठने वाली आवाजों को नजरअंदाज करना किसी भी दल के लिए आसान नहीं होगा। दूसरी ओर, आरक्षण केवल चुनावी मुद्दा नहीं है।

यह संविधान, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय से जुड़ा प्रश्न है। इसलिए इस विषय पर राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि वे आरक्षण व्यवस्था को लेकर क्या सोचते हैं, उसकी कमियों को कैसे दूर करेंगे और सामान्य वर्ग के युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार किस प्रकार करेंगे।

यही वह क्षेत्र है जहां 2027 की राजनीति में भावनाओं के बजाय नीतियों की परीक्षा हो सकती है।

‘पीडीए’ की राजनीति और बदलता सामाजिक गणित

समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक—पीडीए—के सामाजिक समीकरण को अपनी राजनीति के केंद्र में रखा है। कांग्रेस भी सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक विमर्श में प्रमुखता देती रही है।

लेकिन सामाजिक समीकरण केवल जातीय गणित से स्थायी नहीं होते। मतदाता यह भी देखता है कि उसके सामने शासन का मॉडल क्या है, रोजगार की संभावनाएं क्या हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है तथा कानून-व्यवस्था को लेकर उसका अनुभव क्या है।

इसीलिए 2027 की लड़ाई में ‘कौन किस जाति के साथ है’ से आगे बढ़कर यह प्रश्न महत्वपूर्ण होगा कि कौन किस वर्ग के लिए क्या करेगा?

बसपा के सामने अस्तित्व और पुनर्स्थापना की चुनौती

बहुजन समाज पार्टी कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में निर्णायक शक्ति हुआ करती थी। 2007 में उसने सामाजिक समीकरणों को साधते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। लेकिन बाद के चुनावों में उसका राजनीतिक प्रभाव घटा।

2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को केवल एक सीट मिली। इसके बावजूद दलित राजनीति में उसका ऐतिहासिक प्रभाव पूरी तरह समाप्त मान लेना जल्दबाजी होगी। इसी सामाजिक आधार में नए नेतृत्व के उभार ने भी प्रदेश की राजनीति को प्रभावित किया है।

नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद की जीत ने दलित राजनीति के भीतर नेतृत्व के नए आयाम को सामने रखा। अब प्रश्न यह है कि बसपा अपने पुराने सामाजिक आधार को किस तरह पुनर्गठित करती है और क्या वह 2027 में किसी बड़े सामाजिक समीकरण की धुरी बन पाती है।

मुस्लिम मतों पर भी रहेगी निगाह

उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। समाजवादी पार्टी लंबे समय से इस वर्ग में मजबूत राजनीतिक समर्थन का दावा करती रही है। लेकिन कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों की सक्रियता इस सामाजिक समूह के भीतर राजनीतिक विकल्पों को प्रभावित कर सकती है।

ऐसे में विपक्ष के सामने केवल भाजपा को चुनौती देने का प्रश्न नहीं होगा, बल्कि अपने-अपने सामाजिक आधार को बनाए रखने की चुनौती भी होगी। सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न बन सकता है। लोकसभा चुनाव में दोनों दलों के गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव का सामाजिक और स्थानीय गणित अलग होता है। विधानसभा में प्रत्येक सीट का स्थानीय समीकरण अधिक निर्णायक हो जाता है।

भाजपा के सामने भी कम चुनौतियां नहीं

भाजपा के लिए 2027 का चुनाव केवल उपलब्धियों को गिनाने का अवसर नहीं होगा। उसे रोजगार, परीक्षा व्यवस्था, महंगाई, किसानों की आय, युवाओं की आकांक्षाओं और सामाजिक असंतोष जैसे सवालों का जवाब भी देना होगा।

कानून-व्यवस्था और विकास सरकार के प्रमुख दावे हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में सरकार के काम का मूल्यांकन विपक्षी आरोपों के साथ-साथ जनता के रोजमर्रा के अनुभवों से होता है।

युवा मतदाता विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा। मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर में राजनीतिक संदेश कुछ ही घंटों में प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाता है। इसलिए 2027 का चुनाव केवल मैदान में नहीं, डिजिटल मंचों पर भी लड़ा जाएगा।

नैरेटिव की लड़ाई होगी निर्णायक:

2024 के लोकसभा चुनाव ने यह दिखाया कि चुनाव में नीतियों और उपलब्धियों के साथ राजनीतिक नैरेटिव की भी बड़ी भूमिका होती है। संविधान और आरक्षण को लेकर विपक्षी दलों के अभियान ने चुनावी बहस को प्रभावित किया था।

भाजपा ने इन आरोपों का खंडन करते हुए संविधान और आरक्षण की रक्षा का अपना पक्ष रखा था। 2027 में भी ऐसे नैरेटिव सामने आएंगे। लेकिन मतदाता के सामने अब केवल आरोप और प्रत्यारोप नहीं, बल्कि ठोस सवाल होंगे—रोजगार कैसे बढ़ेगा? सरकारी परीक्षाओं की व्यवस्था कैसे सुधरेगी?

शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बेहतर होगी? आरक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता कैसे आएगी? युवाओं को अवसर कैसे मिलेंगे? और विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचेगा? इन सवालों के ठोस उत्तर ही चुनावी विमर्श को दिशा दे सकते हैं।

2027 से 2029 तक की राजनीतिक यात्रा

उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2029 के लोकसभा चुनाव से अलग नहीं देखा जा सकता। राज्य की 80 लोकसभा सीटें राष्ट्रीय राजनीति में इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती हैं। 2024 के परिणामों ने दिखाया कि उत्तर प्रदेश में सीटों का संतुलन बदलने पर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक तस्वीर भी प्रभावित होती है।

लेकिन 2027 को 2029 का सीधा पूर्वाभ्यास मानना भी उचित नहीं होगा। विधानसभा चुनाव में स्थानीय नेतृत्व, उम्मीदवार, क्षेत्रीय मुद्दे और सरकार के प्रत्यक्ष प्रदर्शन की भूमिका अधिक होती है। इसलिए 2027 में बनने वाले राजनीतिक समीकरण 2029 के लिए संकेत अवश्य देंगे, पर उनका अंतिम परिणाम पहले से तय मानना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सरल करके देखने जैसा होगा।

उत्तर प्रदेश की जनता के सामने अब अनेक प्रश्न हैं और हर दल अपने उत्तर के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। आरक्षण और सामाजिक न्याय के प्रश्न हों या रोजगार और शिक्षा के; कानून-व्यवस्था हो या विकास; जातीय समीकरण हों या नए युवा मतदाता—इन सभी के बीच 2027 का चुनाव प्रदेश की राजनीतिक चेतना की परीक्षा भी होगा।

अंततः लोकतंत्र में पटकथा कोई एक दल नहीं लिखता। पटकथा जनता लिखती है—अपने अनुभव, अपेक्षाओं, असंतोष और विश्वास से। उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में जिस मुद्दे को प्राथमिकता देगी, वही प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करेगा। और उस दिशा की गूंज 2029 की राष्ट्रीय राजनीति में भी सुनाई पड़ सकती है।

विशेष लेख

श्वेत क्रांति और गो-संरक्षण के क्षेत्र में सिरमौर बनता मध्य प्रदेश



- डॉ. प्रेम व्यास
(प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट, भाजपा, मध्य प्रदेश)

आदरणीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के दूरदर्शी और सार्थक प्रयासों से मध्य प्रदेश में सकारात्मक परिवर्तन की नई बयार बह रही है। राज्य सरकार ने ‘कृषि कल्याण वर्ष’ में किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ जो कार्य किए हैं, उनके सुखद परिणाम आज सबके सामने हैं। इसी का प्रतिफल है कि आज मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे पायदान पर मजबूती से खड़ा है। हमारी दुग्ध उत्पादन विकास दर 8 से 12 प्रतिशत के बीच रही है, जिसे 20 प्रतिशत तक ले जाकर मध्य प्रदेश को देश का प्रथम दुग्ध उत्पादक राज्य बनाने का संकल्प अब धरातल पर आकार ले रहा है।

दुग्ध उत्पादन और संग्रहण को सुदृढ़ करने के लिए पूर्व में 11 हजार गांवों को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) से जोड़ा गया था। अब सरकार ने 26,000 गांवों को जोड़ने का प्रारंभिक लक्ष्य रखा है। इससे प्रदेश में दूध का कलेक्शन, कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज और वैल्यू एडिशन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इसके साथ ही, किसानों तक पहुंच और सुविधाएं बढ़ाने के लिए दुग्ध समितियों की संख्या भी 6,000 से बढ़ाकर 9,000 की जा रही है।

दूध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘बोनस योजना’, ‘डॉ. भीमराव कामधेनु योजना’, ‘मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना’ और ‘यशोदा मिल्क सप्लाई योजना’ जैसी कल्याणकारी नीतियां प्रदेश के किसानों और पशुपालकों के जीवन में आर्थिक समृद्धि ला रही हैं।

कृषि और दुग्ध उत्पादन के साथ-साथ निराश्रित गोवंश के प्रति मुख्यमंत्री जी ने जो अतिरिक्त संवेदना और महत्व दिखाया है, वह अनुकरणीय है। प्रदेश में वर्तमान में 1 करोड़ 57 लाख से ज्यादा गोवंश हैं। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार प्रदेश में पूर्व में 2190 पंजीकृत गोशालाएं थीं, जो 21वीं गणना में बढ़कर 3214 हो गई हैं (जिसमें 937 नए पंजीयन शामिल हैं)। वर्तमान में 1570 गोशालाएं ‘सीएम गो-सेवा योजना’ के तहत संचालित हैं और लगभग 630 अशासकीय गोशालाएं भी सेवारत हैं।

राज्य सरकार ने गो-सेवा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए गोशालाओं का बजट तीन गुना कर दिया है। प्रति गोवंश आहार अनुदान राशि बढ़ाकर 40 रुपये कर दी गई है (किसी भी अन्य राज्य में यह औसत 50 रुपये से अधिक नहीं है)। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में अभियान चलाकर गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है और अत्याधुनिक गोशालाओं का निर्माण किया जा रहा है।

निराश्रित पशुओं के स्थायी समाधान और आत्मनिर्भर गोशालाओं के निर्माण में मध्य प्रदेश आज देश का पथ प्रदर्शक बन गया है। 2 अक्टूबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्वालियर में बायो-सीएनजी संयंत्र का वर्चुअल उद्घाटन किया था। आज यह संयंत्र अपनी 100 प्रतिशत क्षमता के साथ मुनाफे में काम कर रहा है, जहां मंडी और डेयरी संचालकों से प्रतिदिन 100 टन गोबर पहुंच रहा है। इसी संयंत्र से जुड़ी ग्वालियर की ‘लाल टिपारा’ गोशाला आज देश की पहली अत्याधुनिक और आत्मनिर्भर गोशाला बन गई है, जहां 10,000 निराश्रित गोवंश को पूर्ण सुविधाओं के साथ रखा जा रहा है।

इसी तर्ज पर भोपाल से 20 किलोमीटर दूर 25 एकड़ में ‘बरखेड़ा अब्दुल्ला हाईटेक गोशाला’ बनाई गई है। इको-फ्रेंडली वातावरण वाली इस गोशाला में 10,000 निराश्रित गायों की व्यवस्था है और नियमित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। जबलपुर में 86 एकड़ में 6,000 से अधिक पशु क्षमता वाली प्रदेश की सबसे बड़ी हाईटेक गोशाला का निर्माण हुआ है। इसके अलावा, 5,000 गोवंश की क्षमता वाले ‘कामधेनु निवास’ और स्वावलंबी गोशालाएं भी स्थापित की गई हैं।

प्रदेश में गो-सेवा और श्वेत क्रांति के इस महायज्ञ को और अधिक गति मिलने वाली है। जल्द ही देश के यशस्वी केंद्रीय सहकारिता एवं गृहमंत्री श्री अमित शाह जी प्रदेश के 35,000 गोपालकों एवं ‘गोपालक दीदियों’ को संबोधित करेंगे और उनसे सीधा संवाद करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश को एक बड़ी सहयोग राशि मिलने की प्रबल संभावना है, जिससे इन विकास कार्यों में और अधिक तीव्रता आएगी तथा मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन व गो-संरक्षण के क्षेत्र में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनकर उभरेगा।

विचार लेख



पंडित रविशंकर शास्त्री

पितृ मोक्ष अमावस्या विशेष

सर्वपितृ अमावस्या आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को कहा जाता है, जो पितृ पक्ष (श्राद्ध पक्ष) का अंतिम दिन होता है। इसे ‘सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या’ या ‘महालया अमावस्या’ भी कहते हैं। सरल शब्दों में, यह हमारे सभी पूर्वजों (पितरों) को सम्मान देने और उनकी विदाई करने का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। (सर्वपितृ अमावस्या) के दिन पूर्वजों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करना चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति और मुक्ति मिल सके।

मुख्य कार्य (क्या करें)

तर्पण और पिंडदान: सुबह स्नान करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काले तिल, जौ और कुश मिलाकर पितरों का तर्पण करें।

अज्ञात तिथि पर श्राद्ध:

जिन पूर्वजों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं है, यह हम श्रद्धा नहीं कर पाए हैं पितृपक्ष में तो उनका श्राद्ध इस अमावस्या पर किया जा सकता है। जिन पितरों को गए हुए 1 वर्ष पूरे ना हुए हो और पितृपक्ष आ गया हो तो इस पितृ पक्ष में सिर्फ उनका तर्पण करेंगे श्रद्धा 1 वर्ष पर ही किया जाता है।

पंचबलि भोग:

भोजन का कुछ हिस्सा गाय, कौवे, कुत्ते, चींटी और देवताओं (ब्राह्मण) के लिए निकालें।

श्वान बलि: कुत्ते के लिए भोजन।

काक बलि: कौवे के लिए भोजन (कौवे को पितरों का रूप माना जाता है)।

देवादि बलि:

देवताओं और चींटियों के लिए भोजन।
ब्राह्मण भोज: इसके बाद आदरपूर्वक ब्राह्मणों को सात्विक भोजन कराया जाता है।

दान-पुण्य और दीपदान

महादान: इस दिन अन्न, वस्त्र, जूते, छाता, काले तिल, घी, और सामर्थ्य अनुसार धन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों या ब्राह्मणों को भोजन कराएं, और अन्न, वस्त्र या सतनाजा (सात प्रकार के अनाज) का दान करें।
पीपल के पेड़ की पूजा: पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शाम के समय दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाकर पितरों का ध्यान करें।

“ॐ देवताभ्य: पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नम: स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नम:॥”

पितरों को प्रसन्न करने का मंत्र

विचार लेख

GeM के 10 साल — भाग 4: L1 बन गए... फिर भी ऑर्डर पक्का नहीं!

● प्रदीप सैनी

GeM की Financial Bid खुली। स्क्रीन पर आपकी Firm के सामने चमक रहा है—L1। Seller खुश—“सबसे कम Rate मेरा है, अब Order भी मेरा।”

लेकिन सरकारी खरीद में L1 कई बार मंजिल नहीं, सिर्फ अगला पड़ाव होता है। सबसे कम Rate देने के बाद भी पूरा Order किसी एक Seller को मिले, यह जरूरी नहीं। और इससे भी दिलचस्प बात—कुछ परिस्थितियों में L2 या उससे ऊपर का Seller भी L1 Rate match करके Order का हिस्सा पा सकता है।

L1 नहीं, फिर भी Order? MSE का L1+15% नियम

केंद्र सरकार की Public Procurement Policy for MSEs के तहत, जहां यह preference लागू होती है, यदि L1 कोई non-MSE है और पात्र Micro/Small Enterprise का quoted price L1 से 15% तक अधिक है, तो उस MSE को L1 Rate match करने का अवसर मिल सकता है। निर्धारित परिस्थितियों में उसे tendered value का हिस्सा दिया जा सकता है।

मान लीजिए L1 Rate ₹100 है और पात्र MSE ने ₹114 Quote किया। केवल ₹14 ज्यादा होने का मतलब यह नहीं कि वह हमेशा खेल से बाहर हो गया—लागू policy के तहत उसे ₹100 match करने का अवसर मिल सकता है।

एक और चौंकाने वाला नियम—Make in India में L1+20%

कुछ केंद्रीय सरकारी procurements में Class-I Local Supplier को भी purchase preference मिलती है। जहां संबंधित Make in India policy लागू हो, वहां निर्धारित परिस्थितियों में L1+20% के price band में आने वाला eligible Class-I Local Supplier, L1 Rate match कर Order का हिस्सा प्राप्त कर सकता है।

यानी ₹100 वाला L1 होना हमेशा 100% quantity मिलने की गारंटी नहीं है। L2 और L3 भी वापस खेल में आ सकते हैं GeM के Bid Splitting provision में Buyer बड़ी quantity, urgent delivery या कई supply sources की जरूरत के अनुसार पहले से घोषित ratio में Order को एक से अधिक suppliers में बांट सकता है। ऐसी स्थिति में L1 को निर्धारित हिस्सा देने के बाद बाकी quantity के लिए L2, L3 आदि को L1 Rate match करने का counter-offer मिल सकता है।

तो अगली बार Financial Result में L2 देखकर तुरंत यह मत मानिए कि कहानी खत्म हो गई। और बीच में आ जाए Reverse Auction तो? यहीं GeM का एक और दिलचस्प पड़ाव आता है—RA यानी Reverse Auction।

RA में Sellers कीमत बढ़ाते नहीं, बल्कि एक-दूसरे से कम Rate देते जाते हैं। लेकिन एक कम चर्चित बात यह है कि हर technically qualified Seller का RA में जाना जरूरी नहीं। GeM के प्रकाशित GTC में 50% Elimination और H1 Elimination जैसे Bid-to-RA qualification rules दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, 50% rule में यदि 7 bidders technically qualify हों, तो सामान्यतः L1 से L4 तक RA में जा सकते हैं; 2 या 3 qualified bidders होने पर सभी को शामिल किया जाता है। पात्र MSE और Make in India sellers के लिए निर्धारित price bands में कुछ अतिरिक्त provisions भी हैं।

Gem Assets यानी RA शुरू होने से पहले भी Seller को यह समझना चाहिए—“मैं technically qualified हूं” और “मैं RA के लिए qualified हूं”—दोनों हमेशा एक ही बात नहीं।

और RA में सबसे बड़ा खतरा? Competitor को पीछे छोड़ते-छोड़ते Rate इतना नीचे चला जाए कि Order तो मिल जाए, Profit गायब हो जाए।

सबसे हैरान करने वाली बात—Rate बहुत कम हुआ तो भी मुश्किल! Seller अक्सर सोचता है—“जितना कम Rate, उतना अच्छा।”

लेकिन सरकारी procurement framework में Abnormally Low Bid (ALB) की अवधारणा भी है। यदि Rate इतना कम हो कि Buyer को उस कीमत पर contract सफलतापूर्वक पूरा होने पर संदेह हो, तो Seller से detailed price analysis और clarification मांगा जा सकता है। Seller यदि उस Rate की commercial viability स्पष्ट नहीं कर पाए, तो Bid पर सवाल खड़ा हो सकता है।

इसलिए Reverse Auction में केवल यह सोचना कि “एक बार और Rate कम कर देता हूं” खतरनाक हो सकता है। क्योंकि L1 एक ranking है—Profit की guarantee नहीं, और हर परिस्थिति में पूरे Order की guarantee भी नहीं।

और शायद यही GeM के competitive market का सबसे महत्वपूर्ण सबक है—ऑर्डर जीतने के लिए Rate कम करना आसान है, लेकिन ऐसा Rate देना जो निभाया भी जा सके—वही असली कारोबारी समझ है।

अगली कड़ी में—भाग 5
“Technical Bid Reject
हो गई... क्या खेल खत्म?”GeM का वह Representation Window जिसे कई Sellers इस्तेमाल ही नहीं कर पाते—Technical Rejection के बाद मिलने वाले महत्वपूर्ण मौके की पूरी कहानी।

GeM Government e Marketplace
Efficient • Transparent • Inclusive



विरासत में राजनीति, पर चुना सिनेमा का शिखरः

सुपरमॉडल और अभिनेता कपिल खादीवाला का सफर



राजनीतिक विरासत से अलग अपनी पहचान बनाने वाले कपिल खादीवाला ने मॉडलिंग से सिनेमा तक का सफर तय किया। सुपरमॉडल और अभिनेता के रूप में पहचान बनाने के बाद अब वे 'गौरी शंकर गोहरगंज वाले' में दिग्गज कलाकारों के साथ नजर आएंगे।

● प्रकाश त्रिपाठी

भोपाल। मध्य प्रदेश का हृदय कहे जाने वाले मालवा की माटी की तासीर ही कुछ ऐसी है कि यहाँ की गोद में पले-बढ़े युवाओं ने हर क्षेत्र में सफलता के नए कीर्तिमान रचे हैं।

जब बात कला, संस्कृति और सिनेमा की आती है, तो अहिल्याबाई होल्कर की नगरी इंदौर ने देश को कई ऐसे नायाब हीरे दिए हैं, जिन्होंने अपनी चमक से पूरी दुनिया को रोशन किया है। 'देश दर्पण संवाद' के हमारे लोकप्रिय और विशेष साप्ताहिक पृष्ठ 'अतिथि देवो भवः' में इस बार हमारे मेहमान मालवा के एक ऐसे ही होनहार लाल हैं– मशहूर सुपरमॉडल, अभिनेता और एक्स मिस्टर इंडिया इंटरनेशनल, श्री कपिल खादीवाला।

एक ऐतिहासिक राजनीतिक विरासत और गांधी परिवार से आत्मीयता कपिल खादीवाला का पारिवारिक बैकग्राउंड बेहद रसूखदार और ऐतिहासिक रहा है।

वे इंदौर के प्रथम सांसद और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल खादीवाला जी के पोते हैं। देश के राजनीतिक इतिहास में खादीवाला परिवार का अपना एक अलग और बेहद मजबूत मुकाम रहा है। देश की सत्ता के शीर्ष पर रहे गांधी परिवार के साथ इस घराने के रिश्ते हमेशा से बेहद करीबी और पारिवारिक रहे हैं।

जहाँ एक ओर उनके लिए राजनीति का एक स्थापित मंच पूरी तरह तैयार था, वहीं कपिल ने अपने दादा जी और परिवार के नाम का सहारा लेने की बजाय, अपनी पहचान खुद बनाने का संकल्प लिया। सिनेमा के प्रति उनके इसी जुनून को उनके ये शब्द पूरी तरह सार्थक करते हैं, "सियासत मेरे खून में हो सकती है, लेकिन मेरी रूह में सिनेमा बसता है..."।

इंटरनेशनल रैंप से लेकर सिनेमाई सफर का आगाज

सियासत के गलियारों से दूर, कपिल ने अपनी फिटनेस, लुक्स और कड़ी मेहनत के दम पर मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय खिताब अपने नाम कर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई और देश-विदेश के कई बड़े ब्रांड्स के लिए रैंप वॉक किया।

फैशन की दुनिया में शिखर छूने के बाद, उनके भीतर के परिपक्व अभिनेता को दिग्गज डायरेक्टर विवेक शर्मा ने पहचाना, जिन्होंने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म 'भूतनाथ' का निर्देशन किया था। विवेक शर्मा की फिल्म 'अ गेम कॉल्ड रिलेशनशिप' से कपिल ने बतौर लीड एक्टर अपने सिनेमाई सफर का शानदार आगाज किया।

आगामी फिल्म: 'गौरी शंकर गोहरगंज वाले'

इन दिनों कपिल अपनी आगामी हिंदी फीचर फिल्म 'गौरी शंकर गोहरगंज वाले' को लेकर चर्चा में हैं। नीरज व्यास के कुशल निर्देशन में बन रही इस फिल्म में कपिल बॉलीवुड के उन दिग्गज और मंझे हुए कलाकारों के साथ स्क्रीन साझा कर रहे हैं, जिन्हें सिनेमा जगत में 'एक्टिंग का इंस्टीट्यूट' माना जाता है। इस फिल्म में उनके साथ गोविंद नामदेव की दमदार आवाज, बृजेंद्र काला की बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग और मुश्ताक खान का क्लासिक अंदाज देखने को मिलेगा।

इन दिग्गजों के साथ ही शिवांगी वर्मा और अमिका शैल जैसी प्रतिभाशाली अभिनेत्रियां भी फिल्म का अहम हिस्सा हैं। कपिल मानते हैं कि इतने महान कलाकारों के साथ काम करना उनके लिए किसी एक्टिंग स्कूल में जाने जैसा रहा है।



विशेष साक्षात्कार

इस विशेष अंक के लिए 'देश दर्पण संवाद' के कार्यकारी संपादक प्रकाश त्रिपाठी ने श्री कपिल खादीवाला से उनके जीवन, संघर्ष और सिनेमाई सफर पर विस्तृत बातचीत की। प्रस्तुत हैं इस विशेष बातचीत के प्रमुख अंश:

राजनीतिक विरासत और सिनेमा का चुनाव:

प्रश्न 1: "आपके दादा जी स्व. कन्हैया लाल खादीवाला जी इंदौर के प्रथम सांसद रहे और आपका परिवार गांधी परिवार के बेहद करीब माना जाता है। राजनीति का इतना मजबूत और स्थापित मंच होने के बावजूद, आपने ग्लैमर और सिनेमा का यह अनिश्चित और चुनौतीपूर्ण रास्ता क्यों चुना? क्या कभी राजनीति में कदम रखने का खयाल नहीं आया?"

उत्तर: मेरा बचपन से सपना था कि मैं राजनीति में जाऊं, पर मेरी माता जी चाहती थीं कि मैं मॉडलिंग में जाऊं। उनका सपना सच हुआ और मैं एक सक्सेसफुल सुपरमॉडल बना। इसमें मेरे घर वालों ने मेरा काफी सपोर्ट किया। मैं एक राजनीतिक और सामाजिक बैकग्राउंड वाले परिवार से आता हूं; मेरे दादा जी इंदौर के प्रथम सांसद और स्वतंत्रता सेनानी थे, साथ ही मेरी दादी जी भी स्वतंत्रता सेनानी थीं। इसी वजह से मुझे बहुत प्यार और सम्मान मिलता है। लेकिन मैंने हमेशा जीवन में खुद को ग्राउंडेड रखा। मैंने कभी उस विरासत का दिखावा नहीं किया और हमेशा सहज व शांत रहा।

चकाचौंध के पीछे का संघर्ष:

प्रश्न 2:"महज़ 18 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर का वह प्रतिष्ठित खिताब जीतना और इंटरनेशनल रैंप पर वॉक करना एक बहुत बड़ा मुकाम था। लेकिन इस चकाचौंध भरी सफलता के पीछे आपके उस संघर्ष के बारे में बताएं, जिसके बारे में दुनिया शायद नहीं जानती?"

उत्तर: मैंने महज़ 18 साल की उम्र में सबसे कम उम्र में वह अंतरराष्ट्रीय खिताब जीता था। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि अंदर से मैं बहुत गंभीर इंसान हूं। मुझे शोर-शराबा पसंद नहीं है। मैंने चकाचौंध का जीवन देखा है, लेकिन मैं हमेशा भीड़भाड़ से दूर रहता हूं। सुपरमॉडल बन जाने के बाद भी काम आसान नहीं था। एक ब्रेकथ्रू पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उस लॉबी में अपनी जगह बनानी पड़ती है। इस इंडस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण बात है अपनी फिटनेस को बनाए रखना और हमेशा पॉजिटिव रहना। आपके पास काम हो या ना हो, आपको हमेशा सुपरस्टार की तरह पॉजिटिव ऊर्जा के साथ रहना पड़ता है।

बॉलीवुड डेब्यू और पहला शॉट:

प्रश्न 3: "आपने अपनी सिनेमाई शुरुआत 'अ गेम कॉल्ड रिलेशनशिप' से की, जिसका निर्देशन 'भूतनाथ' जैसी ब्लॉकबस्टर देने वाले विवेक शर्मा जी ने किया था। अपनी पहली फिल्म और कैमरे के सामने दिए गए अपने जीवन के पहले शॉट की यादें हमारे पाठकों के साथ साझा करें?"

उत्तर: मेरा डेब्यू कोविड के पहले ही हो गया था। 'भूतनाथ' के डायरेक्टर विवेक शर्मा जी के साथ काम करने का मौका मिला। अगर मैं पहले दिन और कैमरे के सामने अपने पहले शॉट की बात करूं, तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट था। मेरी यह फिल्म 'अ गेम कॉल्ड रिलेशनशिप' 14 फरवरी 2020 को पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी, और उसके बाद 2022 में यह एमएक्स प्लेयर पर भी आई, जिसे आप लोग वहां देख सकते हैं। कोविड लगने के बाद मेरे काम में दो-तीन साल का ब्रेक जरूर आया, लेकिन अब मैं कंटिन्यू फिल्में कर रहा हूं।

'गौरी शंकर गोहरगंज वाले' की कहानी:

प्रश्न 4: "आपकी आने वाली फिल्म 'गौरी शंकर गोहरगंज वाले' का टाइटल बहुत ही आकर्षक और एकदम ठेठ देसी लगता है। इस कहानी में ऐसी क्या खास बात थी जिसने आपको इसके लिए हामी भरने पर मजबूर कर दिया? इसमें आपका किरदार किस तरह का है?"

उत्तर: 'गौरी शंकर गोहरगंज वाले' जल्दी ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह एक आउट-एंड-आउट कॉमेडी और बहुत ही आकर्षक फिल्म है। यह पूरी तरह से एक पारिवारिक फिल्म है जिसे सभी वर्ग के लोग—दादा-दादी, बच्चे—सब एक साथ बैठकर देख सकते हैं। यह बहुत ही शानदार कॉमेडी फिल्म है, वैसी ही जैसी आपने पहले धर्मेंद्र जी और अमिताभ बच्चन जी की 'चुपके-चुपके' देखी होगी। बहुत समय बाद सिनेमा में ऐसी साफ-सुथरी कॉमेडी फिल्म आ रही है।

दिग्गजों के साथ काम करने का अनुभव:

प्रश्न 5:"नीरज व्यास जी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में आप गोविंद नामदेव जी, बृजेंद्र काला जी और मुश्ताक खान जी जैसे अभिनय जगत के दिग्गजों के साथ काम कर रहे हैं। सेट पर इन 'एक्टिंग इंस्टीट्यूशंस' के साथ आपका तालमेल कैसा रहा और एक कलाकार के तौर पर आपने इनसे सबसे बड़ी बात क्या सीखी?"

उत्तर: गोविंद नामदेव जी, बृजेंद्र काला जी जैसे दिग्गज कलाकारों और मुश्ताक खान जी जैसे शानदार एक्टर (दुर्भाग्य से कुछ दिन पहले ही मुश्ताक जी का निधन हो गया) के साथ काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सेट पर बहुत मजा आया। ये सभी अपने आप में 'एक्टिंग इंस्टीट्यूशन' हैं। ये इतने महान कलाकार हैं कि इन्होंने सेट पर मुझे इतना कंफर्टेबल करा दिया कि मैं बड़े आराम से उनके साथ अपनी एक्टिंग करके निकल गया। इनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीया दिखाने जैसा है।

मध्य प्रदेश और मालवा से जुड़ाव:

प्रश्न 6: "मुंबई की भागदौड़ और चकाचौंध भरी जिंदगी के बीच, इंदौर और मध्य प्रदेश की माटी से आपका जुड़ाव आज भी कितना गहरा है? वहां की कौन सी बातें और कौन सा खानपान आपको मुंबई में सबसे ज्यादा याद आता है?"

उत्तर: मध्य प्रदेश, मालवा और विशेष रूप से इंदौर से मुझे बहुत ज्यादा लगाव है। अगर मुंबई मेरा कर्मक्षेत्र है, तो मेरी मातृभूमि और मेरा दिल इंदौर में ही बसता है। मेरे माता-पिता, मेरी फैमिली इंदौर में है और मेरा बचपन भी वहीं बीता है। मैं भले ही सेलिब्रिटी बन गया, लेकिन मैं हमेशा अपने घर-परिवार और दोस्तों से जुड़ा रहा। मैंने इंदौर कभी नहीं छोड़ा, मेरा वहां हमेशा आना-जाना लगा रहता है। मुझे इंदौर से बहुत प्यार है और वहां जाकर मुझे हमेशा एक प्राउड फीलिंग आती है।

युवाओं के लिए यथार्थवादी सलाह:

प्रश्न 7: "आजकल छोटे शहरों के बहुत से युवा रातों-रात स्टार बनने का सपना लेकर मायानगरी आते हैं। एक सफल सुपरमॉडल और अभिनेता के तौर पर, संघर्ष कर रहे उन युवाओं को आप क्या रियलिस्टिक सलाह देना चाहेंगे?"

उत्तर: इस इंडस्ट्री की सबसे खास बात यह है कि यहां आप रातों-रात स्टार बन सकते हैं, या फिर सालों-साल की मेहनत के बाद भी शायद कुछ न बन पाएं। यहां 90 से 99 प्रतिशत तक लक काम करता है। मैं यह नहीं कह रहा कि आप इस फील्ड में न आएं, लेकिन लक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बहुत जल्दी सुपरमॉडल बन गया था, उस समय मेरा लक बहुत बढ़िया चला। फिर फिल्में मिलीं, कोविड आ गया, तो कुछ चीजें चलती रहीं। मैं मानूंगा कि मेरा लक एवरेज रहा। आज की पीढ़ी और जेन-जी युवाओं को मैं यही बोलना चाहूंगा कि कोई शॉर्टकट न ढूंढें, अपना दिल बड़ा करके इस इंडस्ट्री में आएं। किसी भी असफलता को बहुत जल्दी दिल से न लगाएं। सिर्फ अपने आप को काबिल बनाएं। अगर आप काबिल रहेंगे, तो कामयाबी जरूर मिलेगी; कामयाबी हमेशा एक काबिल आदमी का बाय-प्रोडक्ट होती है।

भविष्य के प्रोजेक्ट्स:

प्रश्न 8: "भविष्य की योजनाओं को लेकर बात करें, तो 'गौरी शंकर गोहरगंज वाले' के बाद आपके और कौन से प्रोजेक्ट्स कतार में हैं? क्या आप ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म या किसी अन्य माध्यम में भी कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हैं?"

उत्तर: 'गौरी शंकर गोहरगंज वाले' तो रिलीज होने ही वाली है, उसके बाद भी कुछ प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं जिनके बारे में अभी मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। डायरेक्टर नीरज व्यास जी के साथ मैं एक और फिल्म कर रहा हूं। एक अन्य फिल्म भी कर रहा हूं जिसकी बहुत जल्द अनाउंसमेंट होने वाली है, इसलिए अभी उसका नाम उजागर नहीं कर सकता। इसके अलावा 'भूतनाथ' के लेखक सुधांशु दुबे जी के साथ भी एक फिल्म कर रहा हूं। ऐसे कंटिन्यू दो-तीन प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है और जल्दी ही आपको मेरा और काम देखने को मिलेगा। अंत में, 'देश दर्पण संवाद' की पूरी टीम का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे 'अतिथि देवो भवः' के इस अंक में जगह दी।

निष्कर्ष

राजनीति के रसूखदार आंगन में बचपन बिताने, इंटरनेशनल रैंप पर तिरंगा लहराने से लेकर बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों के बीच अपनी जगह बनाने तक– कपिल खादीवाला का यह सफर उन तमाम युवाओं के लिए एक बड़ी मिसाल है, जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने का हौसला रखते हैं। 'देश दर्पण संवाद' परिवार की ओर से हम हमारे आज के इस शानदार अतिथि को उनकी आगामी फिल्म 'गौरी शंकर गोहरगंज वाले' की सफलता के लिए ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि वे अपनी कला, सादगी और अभिनय से मालवा, मध्य प्रदेश और पूरे देश का नाम दुनिया भर में इसी तरह रोशन करते रहेंगे।



81 पदकों में लिखी भारत की अब तक की कहानी

शूटिंग से तीरंदाजी, एथलेटिक्स से मुक्केबाजी और कुश्ती से हॉकी-कबड्डी तक, भारत ने एशियाई खेलों में हर मोर्चे पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। 19 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य पदकों की यह यात्रा सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि रिकॉर्ड, संघर्ष, इतिहास और उन खिलाड़ियों की मेहनत है जिन्होंने तिरंगे को गौरवान्वित किया।



● मयंक आनंद

दिल्ली। एशियाई खेलों में भारत की कहानी सिर्फ पदकों की गिनती नहीं है। यह उन अलग-अलग मैदानों की कहानी है, जहां हर दिन किसी नए खिलाड़ी ने तिरंगे को ऊपर उठाया। कहीं निशाना साधते हाथ नहीं कांपे, कहीं आखिरी सेकंड तक दौड़ते कदम नहीं रुके और कहीं बरसों का इंतजार एक जीत के साथ खत्म हुआ। 3 अक्टूबर को पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण जरूर जोड़ा, लेकिन उससे पहले भारत की पदक यात्रा कई खेलों में अपनी पहचान बना चुकी थी।

शुरुआत में ही शूटिंग ने भारत को भरोसा दिया। एलावेनिल वलारिवन, हिमांशु ढिल्लों, रुद्रांक्ष पाटिल और ईशा सिंह जैसे निशानेबाजों ने अलग-अलग स्पर्धाओं में पदक दिलाए। टीम इवेंट्स में भी भारत लगातार पोडियम तक पहुंचा। बंदूक की नली से निकली हर सटीक गोली जैसे भारतीय अभियान को एक और मजबूत आधार देती चली गई।

उस सटीकता की अगली तस्वीर तीरंदाजी में दिखाई दी। महिला कंपाउंड टीम, मिश्रित कंपाउंड टीम और पुरुष कंपाउंड टीम के स्वर्ण के बाद रिकर्व में भी भारत ने बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं। 17 साल की कुमकुम मोहोड़ ने 3 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया की ओह ये-जिन को शूट-ऑफ में हराकर व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण जीता। वह एशियाई खेलों में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। उसी दिन नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व में कांस्य जीता।

कुमकुम की जीत के बाद नजरें उन खिलाड़ियों पर गईं जिनके लिए जीत का मतलब सिर्फ पदक नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत का जवाब था। मीराबाई चानू ने 49 किग्रा भारवर्ग में रजत जीता, जबकि तुशू में रोशिबिना देवी ने भी रजत अपने नाम किया। दोनों पदक अलग-अलग खेलों से आए, लेकिन मंच पर तिरंगा वही था।

ट्रैक पर भारत की कहानी और लंबी हुई। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर और 1500 मीटर में रजत के साथ-साथ 5000 मीटर और मिश्रित 4x100 मीटर रिले में कांस्य भी जीता। अंसी सोजन, सरवेश कुशारे, तजिंदरपाल सिंह तूर, मुरली श्रीशंकर और यशवीर सिंह ने भी एथलेटिक्स में भारत की पदक सूची बढ़ाई। महिलाओं की 400 मीटर, 400 मीटर हर्डल्स, 5000 मीटर, 10,000 मीटर, पोल वॉल्ट और हाई जंप में भी भारतीय एथलीट पोडियम तक पहुंचे।

मैदान से रिंग में पहुंचे तो लवलीना बोरगोहेन, परवीन हुड्डा और अंकुश पंघाल ने मुक्केबाजी में स्वर्ण दिलाए। इनके साथ प्रिय घंघास, कपिल पोखरिया और नरेंद्र बरवाल ने कांस्य जीते। कुश्ती में सुजीत कलकल ने स्वर्ण और नितेश सिवाच तथा सुनील कुमार ने रजत-कांस्य के जरिए भारत की ताकत दिखाई।

कुश्ती की जद्दोजहद के बाद टीम खेलों ने कहानी को अलग रंग दिया। महिला और पुरुष कबड्डी टीमों ने स्वर्ण जीते, जबकि भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियाई खेलों का स्वर्ण अपने नाम किया। यह जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर दर्ज एक और स्वर्ण नहीं थी; यह उस टीम की वापसी थी जिसने लंबे समय से इस मंच पर शीर्ष स्थान का इंतजार किया था।

इसी बीच स्क्वैश में अनाहत सिंह और अभय सिंह ने रजत, जबकि टीम और मिश्रित युगल में भारत ने कांस्य जीते। गोल्फ में प्रणवी उर्स ने इतिहास रचते हुए व्यक्तिगत स्वर्ण जीता और अदीति अशोक व दीक्षा डागर के साथ महिला टीम ने रजत हासिल किया। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, रोइंग, सेलिंग, सॉफ्ट टेनिस, कुराश, सेपकटकरॉ और एमएमए में आए कांस्य पदकों ने भी इस अभियान में अपनी जगह बनाई।

और फिर आया वह मुकाबला, जिसका इंतजार पूरे एशिया को था। भारत बनाम पाकिस्तान, एशियाई खेलों का पुरुष क्रिकेट फाइनल। भारत ने 211/6 बनाए और पाकिस्तान को 192/6 तक रोककर 19 रन से स्वर्ण जीत लिया। अभिषेक शर्मा के 61 और तिलक वर्मा के नाबाद 51 रन ने जीत की नींव रखी।

लेकिन इस बार असली जीत सिर्फ क्रिकेट की नहीं है। 19 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य—कुल 81 पदक भारत की उस यात्रा का हिसाब हैं, जिसमें हर खेल की अपनी कहानी है।

किसी ने रिकॉर्ड बनाया, किसी ने इतिहास रचा, किसी ने पदक जीतकर तिरंगा उठाया और किसी ने पोडियम से चूककर भी अपना सब कुछ मैदान पर छोड़ दिया। एशियाई खेल खत्म होने से एक दिन पहले भारत के खाते में यही सबसे बड़ी तस्वीर है—एक टीम नहीं, कई खेलों से मिलकर बना पूरा भारत।



मनोरंजनम्

‘द वन’ के ‘छठी मैया’ गीत ने सिनेमाघरों को बनाया मंदिर, हॉल में पॉपकॉर्न की जगह बंटा ठेकुआ



दिल्ली। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया इन दिनों अपनी नई फिल्म ‘द वन’ को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में उनका किरदार और विशेष रूप से ‘छठी मैया’ गाना दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

दर्शक इस फिल्म को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर नहीं, बल्कि एक पर्व की तरह देख रहे हैं। ‘द वन’ में तमन्ना का किरदार आस्था और लोककथाओं से गहराई से जुड़ा है।

सिनेमाघरों का माहौल इस वक्त किसी चमत्कार से कम नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल रील्स और वीडियो में देखा जा सकता है कि दर्शक सिनेमाघर के बाहर अपने जूते-चप्पल उतारकर अंदर जा रहे हैं।

हॉल के अंदर लोग पॉपकॉर्न छोड़कर छठ का प्रमुख प्रसाद ‘ठेकुआ’ बांट रहे हैं। बिहार, पटना और झारखंड से फिल्म को भारी समर्थन मिल रहा है, जहाँ कई लोग थिएटर में अपनी आस्था के चलते भावुक होकर रो रहे हैं।

छठ महापर्व से अपने भावनात्मक जुड़ाव, स्पिरिचुअलिटी और सनातन पर बात करते हुए तमन्ना भाटिया ने कहा कि दर्शकों का यह रिएक्शन उनके लिए बहुत मैजिकल है। उन्होंने बताया, “करीब चार साल पहले जब मैं अपने गुरु से मिली, तब मेरी असल स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। अगर यह फिल्म मुझे 4 साल पहले ऑफर होती, तो शायद मैं इसे उस तरह नहीं कर पाती”।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भक्ति के भाव में कोई मिलावट या झूठी एक्टिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि भाव सच्चा न होने पर दर्शक तुरंत पकड़ लेते हैं। तमन्ना ने पटना का एक किस्सा भी साझा किया, जहां एक स्टूडेंट ने उनसे कहा था कि वह यह गाना इसलिए कर पाईं क्योंकि ऊपर वाले ने उन्हें इसके लिए चुना है।



‘दृश्यम 3’: 2 अक्टूबर का तिलिस्म टूटा, अब 23 जुलाई की नई बिसात पर होगा विजय सालगांवकर का ‘चेकमेट’



● प्रकाश त्रिपाठी

इंदौर | सिनेमाई इतिहास में 2 अक्टूबर और स्वामी चिन्मयानंद आश्रम की कहानी को एक कल्ट (Cult) का दर्जा दिलाने वाली फ्रेंचाइजी ‘दृश्यम’ अब अपने अंतिम और निर्णायक पड़ाव पर पहुंच गई है।

‘दृश्यम 3’ के हालिया रिलीज हुए कंक्लूजन पार्ट ने दर्शकों और पुलिस सिस्टम, दोनों के दिमाग में एक नई उलझन पैदा कर दी है। अब तक जो सस्पेंस 2 अक्टूबर के इर्द-गिर्द बुना गया था, उसका तिलिस्म टूट चुका है और अब सारा खेल 23 जुलाई की एक नई और रहस्यमयी तारीख पर आ टिका है।

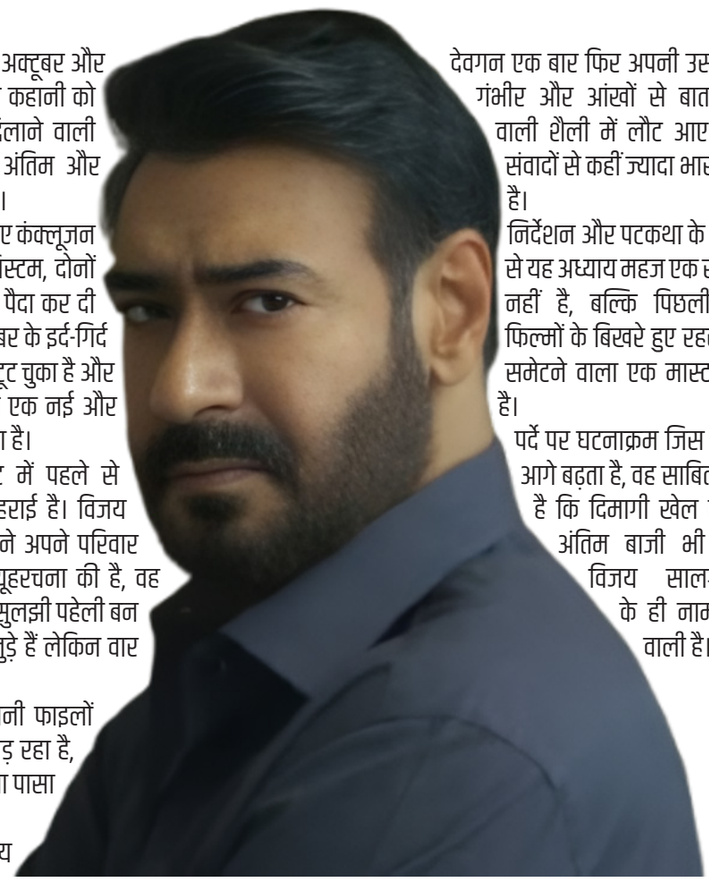
इस बार कहानी की बुनावट में पहले से कहीं अधिक कसावट और गहराई है। विजय सालगांवकर (अजय देवगन) ने अपने परिवार को बचाने के लिए जो नई व्यूहरचना की है, वह सिस्टम के लिए एक ऐसी अनसुलझी पहेली बन गई है, जिसके तार अतीत से जुड़े हैं लेकिन वार भविष्य पर हो रहा है।

जब पूरा पुलिस महकमा पुरानी फाइलों और 2 अक्टूबर के सायों से लड़ रहा है, तब विजय ने 23 जुलाई का नया पासा फेंककर सबको चौंका दिया है।

अभिनय के मोर्चे पर अजय देवगन एक बार फिर अपनी उसी शांत, गंभीर और आंखों से बात करने वाली शैली में लौट आए हैं, जो संवादों से कहीं ज्यादा भारी पड़ती है।

निर्देशन और पटकथा के लिहाज से यह अध्याय महज एक सीक्वल नहीं है, बल्कि पिछली दोनों फिल्मों के बिखरे हुए रहस्यों को समेटने वाला एक मास्टरस्ट्रोक है।

पर्दे पर घटनाक्रम जिस गति से आगे बढ़ता है, वह साबित करता है कि दिमागी खेल की यह अंतिम बाजी भी अंततः विजय सालगांवकर के ही नाम रहने वाली है।



रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत की पहल को यूक्रेन की हरी झंडी



नई दिल्ली। रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने की कोशिशों के बीच भारत की कूटनीतिक भूमिका अब पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण होती दिख रही है। यूक्रेन ने भारत की ओर से शांति के लिए दिए गए प्रस्ताव को चार मौजूदा अंतरराष्ट्रीय पहलों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने 2 अक्टूबर को कहा कि भारत ने युद्ध को खत्म करने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने की इच्छा जताई है।

भारत की पहल का एक अहम हिस्सा ब्लैक सी में ऊर्जा आपूर्ति और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा से जुड़ा है। युद्ध के दौरान ब्लैक सी क्षेत्र में ऊर्जा और समुद्री व्यापार से जुड़ी सुविधाएं लगातार प्रभावित हुई हैं। ऐसे में इन इलाकों में अस्थायी युद्धविराम की व्यवस्था बनाना रूस और यूक्रेन के बीच भरोसा कायम करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है।

यूक्रेन ने संपर्क और मध्यस्थता के लिए भारत की कोशिशों का स्वागत ऐसे समय किया है, जब युद्ध को खत्म करने के लिए कई अलग-अलग प्रस्ताव सामने आ रहे हैं। भारत लंबे समय से दोनों पक्षों के बीच बातचीत और कूटनीति को ही समाधान का रास्ता बताता रहा है। अब उसकी भूमिका केवल दोनों देशों से संवाद बनाए रखने तक सीमित नहीं दिख रही, बल्कि वह ठोस मध्यस्थता प्रस्ताव के साथ सामने आने की कोशिश कर रहा है।

भारत के लिए यह पहल रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। रूस के साथ उसके पुराने रक्षा और ऊर्जा संबंध हैं, जबकि अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ भी भारत की साझेदारी लगातार मजबूत हुई है। ऐसे में दोनों पक्षों के साथ संवाद बनाए रखने की भारत की क्षमता उसे एक संभावित मध्यस्थ की स्थिति में ला सकती है।

हालांकि, भारत की पहल की असली परीक्षा रूस की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। यूक्रेन की सकारात्मक प्रतिक्रिया से रास्ता जरूर खुला है, लेकिन किसी भी शांति योजना को सफल बनाने के लिए मॉस्को और कीव दोनों की सहमति जरूरी होगी।

फिलहाल इतना साफ है कि युद्ध के समाधान में भारत की आवाज अब सिर्फ एक बाहरी पर्यवेक्षक की नहीं, बल्कि संभावित कूटनीतिक मध्यस्थ की तरह सुनी जा रही है।

इस पहल का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत किसी एक पक्ष के साथ खड़े होने के बजाय दोनों देशों के बीच संवाद का रास्ता खुला रखने पर जोर दे रहा है।

रूस के साथ भारत के लंबे रणनीतिक संबंध हैं, जबकि यूक्रेन और यूरोपीय देशों के साथ भी आर्थिक और कूटनीतिक संपर्क बढ़े हैं। यही संतुलन भारत को बातचीत के लिए अपेक्षाकृत स्वीकार्य पक्ष बना सकता है।

भारत की कोशिश केवल युद्ध रोकने तक सीमित नहीं है। संघर्ष लंबा खिंचने से खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है। खासकर विकासशील देशों के लिए महंगी ऊर्जा और खाद्य वस्तुओं की कीमतें बड़ी चुनौती बनी हुई हैं।

ऐसे में युद्धविराम की कोई भी पहल केवल यूरोप की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण होगी।

हालांकि, कूटनीति की राह आसान नहीं है।

रूस और यूक्रेन के बीच क्षेत्रीय विवाद, सुरक्षा गारंटी और युद्ध के बाद की व्यवस्था जैसे मुद्दे अब भी सबसे बड़ी अड़चन हैं।

भारत की पहल को आगे बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों का भरोसा हासिल करना जरूरी होगा। आने वाले दिनों में यही तय करेगा कि भारत की यह पहल सिर्फ ए

G7 का बड़ा फैसला, बाजार में आएगा 10 करोड़ बैरल तेल और डीजल

पश्चिम एशिया संकट और सप्लाई बाधित होने से बढ़ी कीमतों के बीच आपातकालीन भंडार खोलने पर सहमति, अगले चार महीनों में होगी सप्लाई

दिल्ली। दुनिया के सात सबसे विकसित देशों के समूह G7 ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में बढ़ते दबाव को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 2 अक्टूबर को फ्रांस की अध्यक्षता में हुई आपातकालीन वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद G7 देशों ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में 10 करोड़ बैरल तक कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद, खासकर डीजल, अपने रणनीतिक भंडार से जारी करने पर सहमति जताई है। यह रिलीज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) के समन्वय में होगी और अगले चार महीनों में पूरी की जाएगी।

इस फैसले की सबसे अहम बात यह है कि डीजल की सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा शुरुआती 20 दिनों में ही बाजार में उतारने की योजना है। G7 का मकसद अचानक बढ़ी कीमतों को नियंत्रित करना और उन उद्योगों, कारोबारों तथा आम लोगों को राहत देना है, जो महंगे ईंधन की वजह से बढ़ती लागत का सामना कर रहे हैं।

तेल बाजार पर क्यों बढ़ा दबाव?

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ी अनिश्चितता ने वैश्विक तेल आपूर्ति पर दबाव बढ़ाया है। यह रास्ता दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जरिए बड़ी मात्रा में तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की आवाजाही होती है। इसके अलावा रूस में रिफाइनरियों पर हमलों और अन्य सप्लाई बाधाओं ने खास तौर पर डीजल बाजार को और तंग कर दिया है। IEA के मुताबिक, कच्चे तेल का मध्य-पूर्व से निर्यात कुछ हद तक सुधरा है, लेकिन रिफाइंड उत्पादों, खासकर डीजल, की सप्लाई अब भी गंभीर दबाव में है।

यही वजह है कि इस बार G7 का फोकस सिर्फ कच्चे तेल पर नहीं, बल्कि डीजल की तत्काल उपलब्धता पर भी है। डीजल परिवहन, खेती, निर्माण और उद्योगों के लिए जरूरी ईंधन है। इसकी कीमत बढ़ने का असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ट्रकों के भाड़े से लेकर खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा की कई वस्तुओं की कीमतों तक पहुंच सकता है।

पहले भी खोले जा चुके हैं रणनीतिक भंडार

G7 का ताजा फैसला मार्च 2026 में IEA के नेतृत्व में किए गए बड़े आपातकालीन तेल रिलीज अभियान से भी जुड़ा है। IEA के कार्यकारी निदेशक फातिह बिरोल ने बैठक में बताया कि मार्च में घोषित 40 करोड़ बैरल के सामूहिक रिलीज में से करीब 32.5 करोड़ बैरल अब तक बाजार में आ चुके हैं। यानी ताजा 10 करोड़ बैरल की रिलीज उसी व्यापक आपातकालीन योजना को आगे बढ़ाती है।

रणनीतिक तेल भंडार सामान्य परिस्थितियों में बाजार में रोजाना इस्तेमाल के लिए नहीं होते। इन्हें युद्ध, प्राकृतिक आपदा या बड़े सप्लाई संकट जैसी असाधारण परिस्थितियों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। इसलिए इतने बड़े पैमाने पर भंडार खोलना इस बात का संकेत है कि G7 मौजूदा ऊर्जा संकट को सामान्य बाजार उतार-चढ़ाव से कहीं गंभीर मान रहा है।

ऊर्जा निर्यात पर रोक नहीं लगाएगा G7

बैठक में G7 देशों ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया। समूह ने आपसी ऊर्जा कारोबार पर निर्यात प्रतिबंध नहीं लगाने पर सहमति जताई है। G7 ने दूसरे तेल उत्पादक देशों से भी ऐसे प्रतिबंधों से बचने की अपील की है, जो बाजार में सप्लाई को और कम कर सकते हैं।

इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि संकट के समय कोई देश अपनी घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए दूसरे देशों को ऊर्जा की सप्लाई अचानक बंद न करे। इसके साथ ही G7 देशों ने अपनी रिफाइनरियों के रखरखाव का समय भी बेहतर तरीके से समन्वित करने की बात कही है, ताकि कई रिफाइनरियां एक साथ बंद न हों और बाजार में ईंधन की कमी और न बढ़े।



भारत के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला

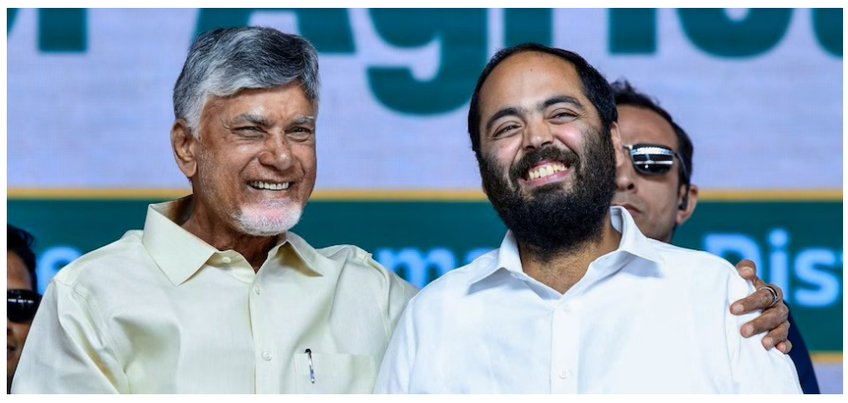
भारत दुनिया के बड़े तेल आयातकों में शामिल है। ऐसे में वैश्विक कच्चे तेल और डीजल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी का सीधा असर देश के आयात बिल और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। सस्ता या स्थिर अंतरराष्ट्रीय तेल भारत के लिए राहत लेकर आ सकता है, क्योंकि इससे ईंधन की लागत, परिवहन खर्च और महंगाई पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।

हालांकि, सिर्फ रणनीतिक भंडार खोलने से ऊर्जा संकट खत्म नहीं होगा। यह बाजार को तात्कालिक राहत देने का उपाय है। यदि पश्चिम एशिया में तनाव लंबे समय तक बना रहता है और तेल आपूर्ति सामान्य नहीं होती, तो आने वाले महीनों में फिर से कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है।

/फिलहाल बाजार की नजर इस बात पर है कि 10 करोड़ बैरल की सप्लाई कितनी तेजी से पहुंचती है और क्या इससे डीजल तथा कच्चे तेल की कीमतों में टिकाऊ गिरावट आती है। G7 का यह फैसला दुनिया को तत्काल राहत देने की कोशिश जरूर है, लेकिन ऊर्जा बाजार की असली परीक्षा तब होगी, जब रणनीतिक भंडार का यह अतिरिक्त तेल बाजार में उतरने के बाद भी पश्चिम एशिया की सप्लाई सामान्य नहीं हो पाती।

व्यापार:-व्यवसाय:

आंध्र प्रदेश में ₹1 लाख करोड़ लगाएगी रिलायंस, 3 लाख से ज्यादा रोजगार का दावा



● कार्तिका गोठवाल

नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आंध्र प्रदेश में अगले कुछ वर्षों के लिए एक बड़ा निवेश प्लान सामने रखा है। कंपनी राज्य में कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्लांट लगाने पर करीब 1 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। रिलायंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने 2 अक्टूबर को मदनपल्ले में आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। कंपनी का कहना है कि इस परियोजना से राज्य में 3 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा हो सकते हैं और आने वाले दशकों में करीब 60 हजार करोड़ रुपये का राजस्व राज्य को मिल सकता है।

इस निवेश की खास बात यह है कि इसका सीधा संबंध सिर्फ ऊर्जा कारोबार से नहीं है। रिलायंस CBG के लिए कृषि अवशेष, पशुओं के गोबर, खाद्य अपशिष्ट और दूसरे जैविक कचरे का इस्तेमाल करना चाहती है। इन्हीं से तैयार होने वाली बायोगैस को शुद्ध करके CBG बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल प्राकृतिक गैस के विकल्प के तौर पर परिवहन, उद्योग और दूसरे व्यावसायिक क्षेत्रों में किया जा सकता है।

यानी खेतों में बेकार समझी जाने वाली चीजें किसानों के लिए कमाई का जरिया बन सकती हैं। फसल अवशेष और जैविक कचरे को ऊर्जा में बदलने से एक तरफ ग्रामीण इलाकों में अतिरिक्त आय के अवसर बनेंगे, वहीं दूसरी तरफ पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने में भी मदद मिल सकती है।

रिलायंस का यह ऐलान आंध्र प्रदेश में कृषि और टेक्नोलॉजी को जोड़ने की बड़ी योजना के साथ आया है। कंपनी राज्य में Rayalaseema Horticulture Hub और Indian School of Agriculture से भी जुड़ रही है। प्रस्तावित कृषि संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन से फसल निगरानी, प्रिसीजन इरिगेशन, रोबोटिक्स और किसानों के लिए बाजार से जुड़ी जानकारी जैसी तकनीकों पर जोर दिया जाएगा।

कंपनी की योजना Jio के डिजिटल नेटवर्क और कृषि प्लेटफॉर्म के जरिए गांवों तक प्रशिक्षण पहुंचाने की भी है। इसके तहत स्थानीय युवाओं को तकनीक की मदद से किसानों तक जानकारी पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित करने की बात कही गई है।

आंध्र प्रदेश के लिए यह निवेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य पहले से बड़े औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। सरकार के मुताबिक, जून 2024 से अब तक राज्य में 388 बड़े प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं, जिनमें 14 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है।

रिलायंस का CBG प्रोजेक्ट अगर तय योजना के मुताबिक आगे बढ़ता है, तो इसका असर सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। यह कृषि कचरे के लिए बाजार, ग्रामीण रोजगार और वैकल्पिक ईंधन—तीनों को एक साथ जोड़ सकता है। हालांकि, इतनी बड़ी निवेश योजना को जमीन पर उतारने की रफ्तार और वास्तविक रोजगार व राजस्व कितना पैदा होता है, यह आने वाले वर्षों में ही साफ होगा।

सुरक्षित निवेश के साथ पाएं तय रिटर्न, 7.5% ब्याज के साथ 115 महीने में दोगुनी हो सकती है रकम; जानिए कौन कर सकता है निवेश और क्या हैं इसके फायदे

पोस्ट ऑफिस की 'किसान विकास पत्र' (KVP) स्कीम: 115 महीने में पैसा होगा दोगुना, सुरक्षित निवेश पर मिल रहा है शानदार रिटर्न

● शिवम शुक्ला



भोपाल। अगर आप इन दिनों अपनी गाढ़ी कमाई को किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर निवेश करने की योजना बना रहे हैं, जहाँ जोखिम कम हो और मुनाफा भी तय हो, तो पोस्ट ऑफिस की 'किसान विकास पत्र' (KVP) स्कीम आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। बाजार के उतार-चढ़ाव और जोखिमों से दूर, यह सरकारी योजना उन निवेशकों के लिए सबसे अधिक लाभकारी मानी जाती है जो बिना किसी चिंता के लंबी अवधि (लॉन्ग टर्म) में स्थिर और निश्चित रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं।

क्या है किसान विकास पत्र योजना?

किसान विकास पत्र (KVP) भारत सरकार द्वारा संचालित एक बेहद लोकप्रिय स्मॉल सेविंग स्कीम (छोटी बचत योजना) है, जो निवेश के मामले में काफी हद तक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की तरह ही काम करती है। इस स्कीम में निवेशकों को कम से कम ढाई साल यानी 30 महीने के लिए अपना पैसा निवेश करना अनिवार्य होता है, जिसे इस योजना का 'लॉक-इन पीरियड' कहा गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आप इस ढाई साल की अवधि के पूरा होने से पहले इस स्कीम से अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं।

इसमें निवेश करने की न्यूनतम राशि 1,000 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि अधिकतम निवेश की कोई सीमा तय नहीं है।

7.5% का आकर्षक ब्याज और रकम डबल होने की गारंटी

वर्तमान में, सरकार इस योजना पर 7.5% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज (कंपाउंड इंटरेस्ट) दे रही है। इस योजना का सबसे बड़ा और प्रमुख आकर्षण यह है कि एक निश्चित समय सीमा के भीतर इसमें निवेश की गई राशि दोगुनी हो जाती है।

मौजूदा ब्याज दर के अनुसार, इस स्कीम की मैच्योरिटी अवधि 115 महीने (यानी करीब 9 साल और 7 महीने) है, जिसमें आपका पैसा डबल हो जाता है।

चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा यह होता है कि हर साल मिलने वाला ब्याज आपके मूलधन में जुड़ जाता है और अगले साल उसी बढ़ी हुई रकम पर ब्याज मिलता है। इसी वजह से तय समय पूरा होने पर निवेश की गई राशि दोगुनी हो जाती है।

हालांकि, ध्यान रहे कि KVP पर ब्याज दर सरकार हर तिमाही में तय करती है और यह दरें समय के साथ बदल भी सकती हैं।

कौन कर सकता है निवेश?

कोई भी भारतीय नागरिक इस सरकारी स्कीम में पैसा लगा सकता है। किसान विकास पत्र में निवेश करने वाले व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 साल होना जरूरी है। हालांकि, यदि कोई नाबालिग इस योजना से जुड़ना चाहता है, तो उसकी तरफ से अभिभावक (गार्जियन) इसमें निवेश कर सकते हैं।

इसके अलावा इसमें जॉइंट अकाउंट (संयुक्त खाता) खोलने की सुविधा भी दी गई है। जो लोग सुरक्षित निवेश चाहते हैं, जो फिक्स रिटर्न पसंद करते हैं और बाजार के जोखिम से बचना चाहते हैं, उनके लिए यह एक शानदार विकल्प है।

आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में ऑनलाइन या ऑफलाइन जाकर आसानी से इसमें निवेश कर सकते हैं।

KVP में निवेश करना काफी आसान है और इसे देशभर के डाकघरों से शुरू किया जा सकता है। निवेश से पहले मौजूदा ब्याज दर, मैच्योरिटी अवधि और समय से पहले निकासी से जुड़े नियमों की जानकारी जरूर लें। ब्याज दरों में सरकार की ओर से समय-समय पर बदलाव किया जा सकता है। इसलिए निवेश का फैसला अपनी वित्तीय जरूरत, लक्ष्य और जोखिम क्षमता को ध्यान में रखकर ही करें।



“हम औरत आज़ाद हैं”

● मयंक आनंद

दिल्ली। महिलाओं के साथ जब भी कुछ गलत होता है, कोई न कोई आवाज़ उठती ही है। कभी वह दबी हुई सिसकी होती है, कभी गुस्से में तनी मुट्ठी, और कभी सड़क पर गूंजता नारा, जिसे सुनकर पूरा शहर पल भर को रुक जाता है। पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में ऐसा ही नज़ारा दिखा। बारिश हो रही थी, सड़कें भीगी थीं, हाथों में थामे पोस्टर गल रहे थे, फिर भी छात्राओं के कदम नहीं रुके। उनकी आवाज़ में डर नहीं था, अपने हक के लिए खड़े होने का हौसला था।

यह प्रदर्शन 21 सितंबर को दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में 17 साल की किशोरी के साथ हुई कथित गैंगरेप की घटना के बाद उपजे आक्रोश का हिस्सा था। घटना के बाद दिल्ली के कई इलाकों में छात्राओं और महिलाओं ने सुरक्षित सार्वजनिक जगहों, बेहतर पुलिसिंग और बेरोकटोक आने-जाने के अधिकार की मांग की। DU के प्रदर्शनों में मिरांडा हाउस, लेडी श्रीराम कॉलेज, गार्गी कॉलेज और कमला नेहरू कॉलेज समेत कई संस्थानों की छात्राएं शामिल हुईं।

पर इस बार विरोध की भाषा थोड़ी अलग थी। नारों में गुस्सा तो था ही, साथ में व्यंग्य भी था और वह बेबाकी भी, जो सीधे रोज़मर्रा की बोलचाल से निकलकर सड़क तक आ पहुंची थी।

“एक कचौरी, दो समोसा, इन मर्दों का क्या भरोसा?” भीड़ में यह नारा गूंजता तो चेहरों पर हल्की मुस्कान आ जाती, लेकिन उसके पीछे का सवाल बेहद गंभीर था। आखिर महिलाओं को अपने ही शहर में इतना सतर्क क्यों रहना पड़ता है? एक और नारा भी खूब सुनाई दिया:
“एक आलू, दो प्याज, भाड़ में जाए मर्द समाज।”
हल्के-फुल्के अंदाज़ के बावजूद ये नारे महिलाओं के खिलाफ हिंसा और पितृसत्तात्मक सोच पर सीधा वार थे। सोशल मीडिया पर भी इनकी तस्वीरें और वीडियो तेज़ी से फैले।
नॉर्थ कैंपस के मार्च में दो नारे सबसे ज़्यादा गूंजे: **“क्यूट नहीं, क्रांति है हम”** और **“हम औरतें आज़ाद हैं।”**
बारिश में भीगती छात्राओं ने साफ कहा कि सुरक्षा के नाम पर महिलाओं की आज़ादी पर पहरा नहीं बिठाया जा सकता। उनका सवाल सीधा था: रात के बाद बाहर निकलने की ज़िम्मेदारी सिर्फ महिलाओं पर ही क्यों डाली जाती है?

ग्राउन्ड रिपोर्ट

पोस्टरों पर भी यही सवाल अलग-अलग तरह से लिखा था। किसी ने लिखा, **“बेटी की लोकेशन नहीं, बेटे का इंटेंट चेक करो।”** किसी ने लिखा, **“रेपिस्ट को अंदर करो, लड़कियों को नहीं।”** कुछ पोस्टरों पर बेहतर स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक परिवहन, सुरक्षित रास्तों और कॉलेजों, हॉस्टलों व पीजी के आसपास सुरक्षा की मांग दर्ज थी।

साउथ कैंपस में हुए शुरुआती प्रदर्शनों में भी छात्राओं ने सिर्फ रेप का मुद्दा नहीं उठाया। उन्होंने पीछा किए जाने, सार्वजनिक जगहों पर बिना इजाज़त महिलाओं की रिकॉर्डिंग और रोज़ के उत्पीड़न पर भी सवाल उठाए। कई छात्राओं ने बताया कि ऐसी घटनाओं के बाद घरवालों की फिक्र बढ़ जाती है और उन्हें बार-बार बताना पड़ता है कि वे सुरक्षित घर पहुंच गई हैं।

यह मार्च उन लड़कियों की साझा आवाज़ था, जो डर के हिसाब से अपनी ज़िंदगी छोटी नहीं करना चाहतीं। उन्हें पढ़ना है, काम करना है, दोस्तों से मिलना है, देर तक लाइब्रेरी में बैठना है, और ज़रूरत पड़े तो रात में सड़क पर भी चलना है।



बारिश रुक जाएगी, पोस्टर सूख जाएंगे, सड़कें फिर पहले जैसी हो जाएंगी। पर छात्राओं का सवाल वहीं खड़ा रहेगा: महिलाओं को सुरक्षित रहने के लिए अपनी आज़ादी क्यों छोड़नी पड़े?





महिलाओं के खिलाफ अपराध : दिल्ली बनाम भारत

आंकड़ा	दिल्ली	भारत
महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराध (2024)	13,396	4,41,534
बलात्कार के दर्ज मामले (2024)	1,058	29,536
भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर	-	64.6 प्रति लाख महिलाएं
बलात्कार मामलों में आरोपी का पीड़िता को जानना	-	96.8%

विविध संवादः

दस साल की मेहनत का नतीजा: विलुप्ति की कगार पर पहुंचे गोडावण को फिर खुले आसमान में मिली उड़ान



एक दशक के संरक्षण प्रयासों के बाद गोडावण की जंगल में वापसी, वैज्ञानिकों की मेहनत से विलुप्तप्राय प्रजाति के पुनर्वास की उम्मीद जगी।

नई दिल्ली/जैसलमेर। भारत ने वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राजस्थान के जैसलमेर स्थित डेजर्ट नेशनल पार्क में पहली बार कैप्टिव-ब्रेड यानी संरक्षण केंद्र में पाले गए दो नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण) को रविवार को जंगल में छोड़ा गया। यह कदम इस गंभीर रूप से विलुप्तप्राय पक्षी को उसके प्राकृतिक आवास में दोबारा बसाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
गोडावण कभी राजस्थान के थार मरुस्थल की पहचान हुआ करता था, लेकिन आवास के लगातार सिकुड़ने, शिकार और बिजली की लाइनों से टकराने जैसी वजहों से इसकी संख्या तेजी से घटती गई। इसके संरक्षण के लिए केंद्र सरकार, राजस्थान वन विभाग और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) ने करीब एक दशक पहले व्यापक संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया था।
इस अभियान में वैज्ञानिकों ने केवल प्रजनन पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि पक्षियों को जंगल में जीवित रहने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया भी विकसित की।
संरक्षण केंद्रों में पैदा हुए गोडावण को विशेष वातावरणमें प्रशिक्षण दिया गया, ताकि वे भोजन तलाशने, प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप ढलने और मानवीय हस्तक्षेप से दूर रहने की क्षमता विकसित कर सकें।
3 अक्टूबर को शुरू हुई प्रक्रिया के बाद 4 अक्टूबर को दो नर गोडावण को खुले प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया। सरकार के अनुसार, इस अनुभव से प्राप्त वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर भविष्य में और पक्षियों को जंगल में छोड़े जाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जाएगा।
यह उपलब्धि केवल एक पक्षी प्रजाति को बचाने की कोशिश नहीं है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक क्षमता, वन्यजीव संरक्षण नीति और थार के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने की प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। लंबे समय बाद गोडावण का फिर से खुले आसमान में लौटना भारत के संरक्षण प्रयासों के लिए एक उम्मीद भरा अध्याय है।

देश दर्पण संवाद | साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र | पंजीयन संख्या : MPHIN/26/A6588 प्रकाशक : असीत पाठक, 25, गोयल ग्रीन कॉलोनी, निपानिया, पोस्ट ऑफिस–विजय नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश–452010 की ओर से स्वामी असीत पाठक के द्वारा प्रकाशित। किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा।
संपादक : असीत पाठक। मुद्रक : पूनम विश्वकर्मा, विश्वकर्मा प्रिंटिंग प्रेस, H. No. 51/1, Village–Padri, Post Office–Gondwali, Block & Tehsil–Waidhan, Singrauli, Madhya Pradesh–486892 से मुद्रित। प्रकाशन स्थल : इंदौर, मध्य प्रदेश।